RNI No. DELMUL/2012/47011

01 अगस्त, 2026 शनिवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 121

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

जो रूट इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान, स्टीफन फ्लेमिंग बने नए कोच 07

संक्षिप्त वार्ता

मौत के 17 घंटे बाद जिंदा हुई महिला

आगरा। आगरा में मौत के करीब 17 घंटे बाद 65 वर्षीय महिला जिंदा हो गईं। अचानक से दामाद का हाथ पकड़ लिया। कहा कि मैं जिंदा हूं। मुझे कहां ले जा रहे। यह सुनते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन ने उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

मामला जिला मुख्यालय से 8 किमी दूर ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का है। दरअसल, महिला लीवर संबंधी बीमारी से पीड़ित थीं। बरेली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बुधवार तडके 3 बजे महिला को मृत घोषित कर दिया था। देर शाम को शव घर लाया गया। रिश्तेदार और परिचित अंतिम दर्शन के लिए जुटे थे। इसी दौरान दामाद अंतिम प्रणाम करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सास के पैर छुए, महिला के शरीर में हलचल हुई और वह जीवित हो गईं।

सेउटा में हजारों लोग सीमा पार कर घुसे, 9 लोगों की मौत

सेउटा। मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में गुरुवार को हजारों प्रवासी अंदर प्रवेश कर गए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बाड़ तोड़कर स्पेन में प्रवेश किया, जिसके दौरान कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। अब स्पेन ने इलाके में मोरक्को के साथ लगी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला लिया है। सेउटा के लोकल अधिकारियों ने मैड्रिड से इमरजेंसी मदद मांगी थी। इसके बाद स्पेन सरकार ने ऐलान किया कि सिविल गार्ड की मदद के लिए आर्म्ड फोर्स भेजी जाएगी ताकि सेउटा शहर में सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज शुक्रवार को इंटीरियर मिनिस्टर फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का के साथ सेउटा का दौरा करेंगे। बॉर्डर पर तैनात सिविल गार्ड एसोसिएशन के प्रमुख रचिद सबीही ने बताया कि हजारों माइग्रेंट्स क्रॉस कर रहे हैं। बॉर्डर पूरी तरह टूट चुकी थी।

मेरिट बनाम माफिया की लड़ाई, परीक्षा प्रणाली को मिलेगा मजबूत कानूनी ढांचा: राघव चड्ढा

नईदिल्ली। राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने विधेयक का जोरदार समर्थन करते हुए इसे देश का पहला समर्पित एंटी-पेपर लीक कानूनी ढांचा बताया। गुरुवार को चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों से पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों की मेहनत, मेरिट और भविष्य को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सरकार संगठित पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर और प्रभावी कार्रवाई के लिए व्यापक कानून लेकर आई है। चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों की आवाज सुनते हुए त्वरित कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने केवल सरकार के मुखिया के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के अभिभावक की तरह छात्रों की पीड़ा को समझा और आवश्यक निर्णय लिए। उनके अनुसार, पेपर लीक होने पर केवल प्रश्नपत्र ही नहीं, बल्कि छात्रों के सपने, आत्मविश्वास और वर्षों की मेहनत भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नीट परीक्षा विवाद के बाद पुनर्परीक्षा, सीबीआई जांच, एसआईटी गठन, आरोपितों की गिरफ्तारी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में प्रशासनिक बदलाव, परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा भविष्य में नीट को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं।

छत्तीसगढ़ में बाढ़ से नदियों में उफान

100 से अधिक गांव बने टापू

रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में लगातार दो दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शिवनाथ, खारुन, इंद्रावती समेत अधिकांश नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है और कई गांव टापू बन गए हैं।

वेब वार्ता, रायपुर

सबसे अधिक प्रभावित बीजापुर जिला है, जहां 70 से अधिक गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। भोपालपटनम में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से 3.10 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि जगदलपुर के पुराने पुल पर जलस्तर चेतावनी स्तर पार कर लगातार बढ़ रहा है।

भोपालपटनम का महाराष्ट्र और तेलंगाना से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित

बाढ़ के कारण भोपालपटनम का महाराष्ट्र और तेलंगाना से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। गंगालूर, बासागुड़ा, मिरतुर, कुटरु और भोपालपटनम क्षेत्र के ग्रामीण मार्ग जलमग्न हैं। नारायणपुर के ब्रेहबेड़ा नाले में पुलिस की बोलेरो फंस गई, जबकि चिकपाल में बचाव दल ने 16 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला।

रिसोर्ट में फंसे चार बच्चों समेत कुल 24 लोगों सुरक्षित निकाला गया

बलौदाबाजार जिले में लगातार बारिश और गंगरेल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से कसडोल के बल्दाकछार स्थित एक निजी रिसोर्ट चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिर गया। रिसोर्ट में फंसे चार बच्चों समेत कुल 24 लोगों सुरक्षित निकाला गया।

बीजापुर में बचाए गए सात पर्यटक

बीजापुर के लंकापल्ली झरना में फंसे सात पर्यटकों में से एक प्रसूता व नवजात बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। देर रात तक वहां अभियान जारी था। बीजापुर जिले में अगले दो दिनों तक स्कूल व आंगनबाड़ी बंद रखने का आदेश दिया है।

अरनपुर-जगरगुंडा मार्ग अगले 48 घंटे के लिए बंद

दंतेवाड़ा में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए अरनपुर-जगरगुंडा मार्ग अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। वर्षा से राजनांदगांव क्षेत्र के प्रमुख जलाशय और बराज लबालब हो गए। सावन के पहले दिन मोंगरा बराज पहली बार ओवरफ्लो हुआ, जिसके बाद सात गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। शिवनाथ और उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं।

अरनपुर-जगरगुंडा मार्ग 48 घंटे के लिए कर दिया गया बंद

टोक्यो पर महाविनाश का खतरा: जापान बना रहा दूसरी राजधानी

टोक्यो। दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर देशों में शुमार जापान अब अपनी पहचान में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सालों से जापान की शान रहे टोक्यो शहर अब देश का इकलौता ताज नहीं रहेगा, क्योंकि जापानी संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसके तहत जापान अब एक नहीं, बल्कि दो-दो राजधानियां बनाने की तैयारी में है। हालांकि संसद के ऊपरी सदन में यह बिल बेहद मामूली अंतर से गिरते-गिरते बचा। यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर जापान को दो-दो राजधानियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, खासकर तब जब टोक्यो पहले से ही एक विश्वस्तरीय मेगासिटी है? इस अभूतपूर्व कदम के पीछे एक डरावना खुलासा है। भूकंप वैज्ञानिकों और एक अन्य रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगले 30 सालों में टोक्यो में 7 से अधिक तीव्रता का भयानक भूकंप आने की 70 फीसदी आशंका है। यदि यह भविष्यवाणी सच साबित होती है, तो पूरा टोक्यो पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और देश का पूरा बैंक सिस्टम एक झटके में ठप्प हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी संभावित तबाही के खौफ से देश को बचाने के लिए जापानी सरकार ने बैकअप के तौर पर दूसरी राजधानी का यह मास्टरप्लान तैयार किया है।

राहुल बोले- युवाओं की आवाज नहीं दबा सकती सरकार

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जेन-जेड यानी युवा पीढ़ी को डराकर चुप नहीं करा सकती। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तथा सोशल मीडिया खातों को बंद कराया जा रहा है।

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह देश के अतीत की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि भारत का भविष्य युवाओं से जुड़ा है। उन्होंने केंद्र से युवाओं के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर सतर्क रहने की बात कही।

दरअसल, नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी छात्रों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किया। इसके अलावा संसद की ओर मार्च करने के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया और बाद में कई छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। आंदोलन से जुड़े कुछ सोशल मीडिया खातों पर कार्रवाई किए जाने की खबरों के बाद भी विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए केंद्र सरकार पर युवाओं के हितों और लोकतांत्रिक अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं, सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसलों को लेकर अपना पक्ष रखा जाता रहा है।

चीन, तिब्बत और नेपाल में कुछ ही घंटों में आ गए चार भूकम्प

नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी हिमालयी क्षेत्र में शुक्रवार तड़के कुछ घंटों के भीतर चार भूकम्पों के झटके महसूस किए गए। चीन, तिब्बत और नेपाल के कई इलाकों में भूकंपीय गतिविधि दर्ज की गई। हालांकि, अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, यह भूकंपीय गतिविधि गुरुवार रात 11 बजकर 25 मिनट से शुक्रवार सुबह 1 बजकर 44 मिनट के बीच दर्ज की गई। इस दौरान सबसे तेज भूकम्प चीन में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। यह झटका शुक्रवार रात 1 बजकर 44 मिनट पर महसूस किया गया और इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले तिब्बत में दो भूकम्प दर्ज किए गए। पहला झटका 4.3 तीव्रता का था, जो गुरुवार रात 11 बजकर 25 मिनट पर आया। इसकी गहराई करीब 130 किलोमीटर बताई गई। इसके बाद रात 12 बजकर 30 मिनट पर तिब्बत में 4.2 तीव्रता का भूकम्प आया, जिसका केंद्र 90 किलोमीटर की गहराई में था। नेपाल में भी आधी रात 1 बजकर 18 मिनट पर 3.4 तीव्रता का भूकम्प दर्ज किया गया। इसकी गहराई करीब 15 किलोमीटर थी। इन झटकों के कारण हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी चीन के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कंपन महसूस किए गए।

जंग की आड़ में भारतीय नागरिकों की जान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से फोन पर बात की। भारतीय ईएएम ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से न केवल सीधी बात की है, बल्कि ब्लैक सी में फंसे 13 भारतीय नाविकों और मर्चेंट जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुनाई। भारत ने दोटूक अंदाज में कहा कि जंग की आड़ में अपने नागरिकों की जान से खिलवाड़ अब ह्यबर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने साफ संदेश दिया कि जब बात उसके नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में जहाजों की आवाजाही की आएगी भारत किसी भी पक्ष की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि नागरिक जहाजों पर हमले चाहे किसी भी तरफ से हों, वो पूरी तरह से ह्यअस्वीकार्यह्ल हैं और भारत ऐसी हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा करता है।

यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से बातचीत के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर खुद इस बातचीत की डीटेल शेयर की। जयशंकर ने लिखा- यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ दोबारा जुड़कर उन्हें खुशी हुई। बातचीत में उन्होंने ब्लैक सी में कमर्शियल शिपिंग और भारतीय नाविकों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने बिना लाग-लपेट के लिखा- किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और भारत स्पष्ट रूप से इनकी निंदा करता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि रूस-यूक्रेन जंग और दुनिया

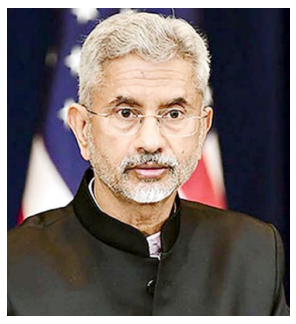

भर में चल रही लड़ाई की वजह से तेल, खाद और राशन की सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी सबसे भारी मार ग्लोबल साउथ यानी गरीब और विकासशील देशों को झेलनी पड़ रही है।

जयशंकर ने कहा कि भारत का हमेशा से यही मानना रहा है कि किसी भी विवाद का हल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकल सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा ने भी इस बातचीत की डीलेट शेयर करते हुए कहा कि डॉ जयशंकर को राष्ट्रपति जेलेंस्की के हालिया वॉशिंगटन दौरे और ट्रंप के साथ हुई बैठक की पूरी जानकारी दी है। सिबिहा ने रूस पर भड़ास निकालते हुए कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर हमले नहीं कर रहा, बल्कि ब्लैक सी में आम जहाजों को निशाना बनाकर समंदर में आने-जाने की आजादी छीन रहा है। इससे पूरी दुनिया में खाने-पीने का संकट खड़ा हो रहा है और तेल-गैस के बाजार में अनिश्चितता फैल रही है। यूक्रेन ने भारत से एक बार फिर गुहार लगाई कि वह इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कराने और शांति कायम करने में अपनी भूमिका निभाए।

इतना ही नहीं, यूक्रेन ने भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की तरफ से जारी की गई सुरक्षा एडवाइजरी पर भी उंगली उठा दी थी। यूक्रेन का तर्क था कि भारत सरकार ने 15 जुलाई को ह्यस्ट्रेट ऑफ होर्मुजह्ल के लिए तो सख्त अलर्ट जारी किया लेकिन 23 जुलाई को ह्यब्लैक सीह्ल के लिए जारी निर्देशों में खतरे को उतना बड़ा नहीं दिखाया। यूक्रेन का दावा था कि रूस ब्लैक सी में नागरिक बंदरगाहों और मालवाहक जहाजों पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, जिससे कई भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं या घायल हुए हैं।

देशभर में एक लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे

नई दिल्ली। देश में बेहतर शिक्षा और सब पढ़ें, सब बढ़ें के बड़े-बड़े दावों के बीच एक हैरान कर देने वाली और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देशभर में एक लाख से भी ज्यादा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो महज एक अकेले शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा दिए गए जवाब से उजागर हुआ यह आंकड़ा दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात का औसतन सही दिखना, जमीनी स्तर पर शिक्षकों की भारी कमी और असमान तैनाती की कड़वी सच्चाई को छिपा देता है। 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1,00,843 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक तैनात है। चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले आंध्र प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां 16,357 स्कूल सिर्फ एक मास्टर के सहारे चल रहे हैं। यह कुल राष्ट्रीय आंकड़े का 16फीसदी से भी ज्यादा है। टॉप 7 राज्य जहां हालात सबसे चिंताजनक हैं उनमें आंध्र प्रदेश: 16,357 स्कूल, झारखंड: 9,827 स्कूल, महाराष्ट्र: 9,269 स्कूल, कर्नाटक: 8,042 स्कूल, उत्तर प्रदेश: 7,874 स्कूल राजस्थान: 7,200 स्कूल, पश्चिम बंगाल: 6,769 स्कूल ये 7 राज्य मिलकर देश भर के कुल सिंगल-टीचर स्कूलों का करीब 65फीसदी हिस्सा बनाते हैं। यह समस्या केवल पिछड़े या दूरदराज के राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के करीब हर हिस्से में फैली हुई है। वहीं तेलंगाना: 4,793 स्कूल, तमिलनाडु: 3,957 स्कूल, असम: 3,159 स्कूल, हिमाचल प्रदेश: 3,128 स्कूल, उत्तराखंड: 2,655 स्कूल, छत्तीसगढ़: 2,461 स्कूल हैं। सबसे बेहतर स्थिति वाले राज्य/यूटी जिसमें दूसरी तरफ केरल में केवल 67, नागालैंड में 35, सिक्किम में 31, लद्दाख में 28, दिल्ली में 7 और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में केवल 1 स्कूल ही ऐसा है जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में औसतन छात्र-शिक्षक अनुपात मानकों के भीतर है। प्राइमरी लेवल: प्रति 19 बच्चों पर 1 टीचर, अपर प्राइमरी: प्रति 17 बच्चों पर 1 टीचर, सेकेंडरी: प्रति 15 बच्चों पर 1 टीचर, हायर सेकेंडरी: प्रति 23 बच्चों पर 1 टीचर हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत आंकड़े असल धरातल की उस विषमता को छिपा देते हैं, जहां एक अकेला शिक्षक स्कूल की प्रशासनिक जिम्मेदारियों, मिड-डे मील की देखरेख और अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर मजबूर है।

संसद में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और स्कूलों में उनकी तैनाती का जिम्मा पूरी तरह से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का होता है। सरकार के मुताबिक पदों के खाली रहने की मुख्य वजह जिसमें शिक्षकों का सेवानिवृत्त होना या इस्तीफा देना, नए पदों का सृजन और पदों का पुनर्गठन, ग्रामीण, आदिवासी और आकांक्षी जिलों में नामांकन के आंकड़ों में लगातार बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से खाली पदों को भरने की सलाह नियमित रूप से दी जाती है और समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई जा रही है।

19 साल बाद कोलकाता लौटेंगी तसलीमा नसरीन

वेब वार्ता, कोलकाता

करीब 19 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेशी लेखिका तसलीम नसरीन एक बार फिर कोलकाता लौट रही हैं। अपनी चर्चित किताब द्विखंडितो को लेकर हुए विरोध और विवाद के बाद वर्ष 2007 में उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा था। अब 1 अगस्त को वह शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिसे वह कभी अपना दूसरा घर मानती थीं। वापसी को लेकर तसलीम नसरीन ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह अपने ही देश लौट रही हैं। उनके अनुसार, बंगाल उनके लिए कभी सीमाओं या कंटीले तारों में बंटा हुआ नहीं रहा। पूर्वी बंगाल का हिस्सा भले ही उनके लिए बंद हो गया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल आज भी उनके लिए अपना घर है।

तसलीम नसरीन ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से कोलकाता नहीं छोड़ा था, बल्कि परिस्थितियों के कारण उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोलकाता केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि वहां उनके दोस्त, पाठक और अपनापन था। उनके मुताबिक, उनसे जीवन के 19 महत्वपूर्ण साल छिन गए, जिनकी भरपाई संभव नहीं है।

लेखिका ने अपनी वापसी को अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि धमकियां और कट्टरपंथी विरोध किसी लेखक को जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने लेखकों के सामने मौजूद मौजूदा चुनौतियों पर भी बात की। तसलीम नसरीन ने कहा कि तकनीक ने जहां विचार व्यक्त करने के नए रास्ते खोले हैं, वहीं ऑनलाइन ट्रोलिंग और संगठित विरोध के जरिए लेखकों को डराने के तरीके भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और परंपरा के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश आज भी जारी है। हालांकि, उन्होंने युवा पीढ़ी और महिलाओं में बढ़ती सवाल करने की प्रवृत्ति को बदलाव की उम्मीद बताया। उनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन विरोध और बहस के जरिए ही आगे बढ़ता है। नई पीढ़ी और नए लेखकों को संदेश देते हुए तसलीम नसरीन ने कहा कि हर मुद्दे पर सवाल करना चाहिए, चाहे वह धर्म, सत्ता, राजनीति या परंपरा से जुड़ा हो।

...आधार न बनाएं

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे दूसरों के पूर्वाग्रहों को अपनी सोच का आधार न बनाएं। तसलीम नसरीन को उम्मीद है कि उनका कोलकाता दौरा केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा और वह भविष्य में इस शहर में बिना किसी डर के आ-जा सकेंगी।

हर कोई धुरंधर नहीं होता, खासकर असम में

वेब वार्ता, गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए 21 कथित अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए असम पुलिस की सतर्कता और दक्षता की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि, हर कोई धुरंधर नहीं होता, खासकर असम में। 21 अवैध घुसपैठियों ने राज्य में

गैरकानूनी रूप से रहने की कोशिश की, लेकिन असम पुलिस ने समय रहते उनकी पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राज्य की सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को निष्प्रभावी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संपादकीय

टूट रहीं संसदीय मयार्दाएं

भारी हंगामे और तीखी नोंकझोंक के बीच लोकसभा में एंटी पेपरलीक संशोधन बिल ध्वनि-मत से पारित करना पड़ा। इस बिल पर 45 सांसदों ने, 10 से ज्यादा घंटे की बहस के दौरान, अपनी बात रखी और संशोधन भी पेश किए, लेकिन बिल पर मत-विभाजन तक नहीं कराया गया। यह लोकतंत्र की सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। बिल हां अथवा ना के शोर में पारित नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि आज भी यही संसदीय व्यवस्था है। उम्मीद थी कि संसद का मानसून सत्र हंगामाखेज होगा, क्योंकि पेपरलीक के अलावा, राम मंदिर में चंदा-चढ़ावा चोरी, ई-20 एथेनॉल विवाद, परिसीमन, दलबदल सरीखे मुद्दे जन-सरोकार, लोकतांत्रिक शुचिता और आम आदमी की आस्था से जुड़े थे। यह भी अपेक्षा की जा रही थी कि जन-सरोकार के इन मुद्दों पर संसद में सार्थक, संरचनात्मक चर्चा होगी, लेकिन पेपरलीक से जुड़े बिल पर ही हमारे सांसदों की क्षुद्र और विरोधाभासी राजनीति बेनकाब हो गई। इसमें सत्ता-पक्ष के सांसद भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। ऐसे एक सांसद ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री दिवंगत जवाहर लाल नेहरू पर ऐसी अभद्र और अश्लील टिप्पणी की, जिसे हम नैतिक रूप से लिखने के भी पक्षधर नहीं हैं। यह न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि संसदीय आचरण और बहस को गर्त में ले जाने वाला भी है। दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, साक्ष्य और प्रमाणित किए बिना ही, बोल दिया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन और बर्बर लाठीचार्ज का आदेश गृहमंत्री अमित शाह ने दिया था। देश के तथाकथित गृहमंत्री युवा, छात्र आंदोलन के बाद कांप रहे थे और वह डरे हुए हैं, लिहाजा सदन में मौजूद नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष को ऐसे आरोपों और शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत ही क्या थी? यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन और प्रदर्शन के वक्त गोलीबारी और घातक लाठीचार्ज का अंतिम निर्णय गृहमंत्री या प्रधानमंत्री लेते हैं। ऐसी संसदीय अज्ञानता पर हम क्या टिप्पणी करें? ऐसे आदेश मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट (डीएम या एसडीएम) ही दे सकते हैं। आपात स्थितियों में पुलिस के डीसीपी या एसीपी को भी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अब यह कैसी संसदीय मयार्दा और विरोधाभास है कि विपक्ष मानता है कि आंदोलित युवाओं पर कीलदार लाठियों से हमले किए गए और पैलेट गन भी चलाई गई, लेकिन बिल पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री दफ्तर में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पैलेट गोलीबारी से साफ इंकार किया है। अलबत्ता आंसू गैस के गोले दागने को जरूर स्वीकार किया है।

वस्तुस्थिति यह है कि एम्स की मेडिकल रपट में पैलेट गन की पुष्टि की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस जिस अस्पताल का उल्लेख कर रही है, उसकी रपट में पैलेट की पुष्टि नहीं की गई है। क्या चिकित्सा के पेशेवर अस्पताल की मयार्दा, नैतिकता और शुचिता भी विरोधाभासी हो गई है, लिहाजा मयार्दाएं खंडित हो रही हैं? एक और तथ्य गौरतलब है कि सीआरपीएफ के विशेष बल आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की डायरी में पैलेट गन चलाने की घटना दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आरएएफ के 12 जवानों के हाथ में पैलेट गन थी। सरकार का बयान भिन्न है, नेता प्रतिपक्ष के आरोप बेहद गंभीर हैं और दिल्ली पुलिस, सुरक्षा बलों के रिकॉर्ड सबसे अलग हकीकत बयां कर रहे हैं! क्या देश की इन व्यवस्थाओं के बीच भी मयार्दा, आचार-संहिता नहीं होनी चाहिए? बहरहाल लोकसभा में बहस हुई, बिल पारित हो गया, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून भी बन जाएगा, लेकिन कई अहम सवाल फिर भी बरकरार रहेंगे। मसलन-शिक्षा का बजट जीडीपी के 4 फीसदी से घटा कर 2.6 फीसदी क्यों किया गया? भारत में औसत शिक्षा 10 गुना महंगी क्यों हो गई है? सरकारी स्कूल में औसतन पढ़ाई का खर्च 2863 रुपए है, जबकि निजी स्कूल में वही खर्च 25,000 रुपए से अधिक क्यों है? कुछ सवाल हमने

भारत में दुग्ध उत्पादन की नई तस्वीर

भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पिछले कुछ दशकों में देश ने जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, उसे श्वेत क्रांति की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। दूध केवल पोषण का स्रोत नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार भी है। देश के लाखों छोटे और सीमांत किसान तथा पशुपालक प्रतिदिन दूध बेचाकर अपनी आय अर्जित करते हैं। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुपालन को आधुनिक बनाने तथा डेयरी उद्योग को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

इसी दिशा में बिहार सरकार भी श्वेत क्रांति को नई गति देने का प्रयास कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन एक करोड़ लीटर दूध उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, उन्नत नस्ल के पशु, पशुपालकों का प्रशिक्षण, पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा डेयरी अवसंरचना को मजबूत बनाया जा रहा है। नालंदा स्थित बिहारशरीफ डेयरी परियोजना परिसर में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले दही एवं लस्सी प्लांट, कॉमफेड संचालित पेट्रोल पंप तथा सुधा कैफेटेरिया का शिलान्यास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। इसी सोच के तहत बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग फेडरेशन बनाने की घोषणा की गई है। बकरी के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था विकसित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री पशु जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पशुपालकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

भारत की दुग्ध क्रांति की शुरूआत वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड से हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की इस महत्वाकांक्षी योजना ने देश को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। आज भारत विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग एक चौथाई से अधिक योगदान देता है। बढ़ती जनसंख्या और पोषण की जरूरतों को देखते हुए दुग्ध उत्पादन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। डेयरी क्षेत्र भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उपक्षेत्र बन चुका है और इसका योगदान कई पारंपरिक कृषि फसलों से भी अधिक हो गया है।

यदि राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है। यहां का वार्षिक दुग्ध उत्पादन लगभग 3 करोड़ 80 लाख टन के आसपास पहुंच चुका है। राज्य में बड़ी संख्या में गाय और भैंसों का पालन होता है तथा डेयरी सहकारी समितियों का मजबूत नेटवर्क किसानों को बाजार उपलब्ध कराता है।

दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यहां का वार्षिक दुग्ध उत्पादन लगभग 3 करोड़ 70 लाख टन के आसपास है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या देश में सबसे अधिक है और यही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी ग्रामीण आबादी और पारंपरिक पशुपालन व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया है।

तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। राज्य का वार्षिक दुग्ध उत्पादन लगभग 2 करोड़ 10 लाख टन है। पिछले कुछ वर्षों में यहां दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार, उन्नत नस्लों का विकास तथा पशुपालन योजनाओं के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चौथे स्थान पर गुजरात है, जहां अमूल मॉडल ने पूरे देश के लिए मिसाल पेश की है। गुजरात का वार्षिक दुग्ध उत्पादन लगभग 1 करोड़ 90 लाख टन है। यहां सहकारी डेयरी आंदोलन ने लाखों किसानों, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। अमूल की सफलता ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाई है। पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां सालाना लगभग 1 करोड़ 80 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। आधुनिक डेयरी फार्म, उन्नत पशुपालन और सरकारी सहायता ने राज्य को तेजी से आगे बढ़ाया है।

छठे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां वार्षिक दुग्ध उत्पादन लगभग 1 करोड़ 50 लाख टन है। राज्य में निजी और सहकारी दोनों प्रकार की डेयरियां सक्रिय हैं और दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है।

सातवें स्थान पर पंजाब है। यहां सालाना लगभग 1 करोड़ 40 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। उच्च उत्पादकता वाली भैंसों और वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों के कारण पंजाब की प्रति पशु दूध उत्पादन क्षमता देश में सबसे अधिक मानी जाती है।

आठवें स्थान पर हरियाणा है, जहां लगभग 1 करोड़ 30 लाख टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन होता है। मुर्रा भैंस जैसी उत्कृष्ट नस्लों ने हरियाणा को डेयरी क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई है।

नौवें स्थान पर बिहार आता है। बिहार का वार्षिक दुग्ध उत्पादन लगभग 1 करोड़ 30 लाख टन के आसपास पहुंच चुका है और इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। कॉमफेड और 'सुधा' ब्रांड की सफलता ने राज्य के डेयरी क्षेत्र को नई दिशा दी है। सरकार की नई योजनाओं से आने वाले वर्षों में बिहार देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में और मजबूत स्थान बना सकता है।

दसवें स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां सालाना लगभग 80 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। राज्य में छोटे पशुपालकों की बड़ी संख्या डेयरी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करती है।

दुग्ध उत्पादन केवल दूध बेचने तक सीमित नहीं है। इससे दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम, मिठाइयों और अनेक मूल्यवर्धित उत्पादों का विशाल उद्योग जुड़ा हुआ है। इस उद्योग से करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक होने के कारण डेयरी क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का भी प्रभावी माध्यम बन गया है।

आज भारत में कृत्रिम गभार्धान, उन्नत नस्लों का विकास, पशु टीकाकरण, डिजिटल डेयरी प्रबंधन, शीत श्रृंखला, दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं और आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों का तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम तथा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बिहार की नई पहल इस व्यापक राष्ट्रीय अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि राज्य अपने प्रतिदिन एक करोड़ लीटर उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी। सुधा ब्रांड का विस्तार, डेयरी प्रोसेसिंग हब, पशु स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक विपणन व्यवस्था बिहार को पूर्वी भारत का प्रमुख डेयरी केंद्र बना सकती हैं।

भारत की श्वेत क्रांति अब केवल दूध उत्पादन बढ़ाने का अभियान नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का सबसे सफल मॉडल बन चुकी है। आने वाले वर्षों में यदि आधुनिक तकनीक, बेहतर नस्लों, वैज्ञानिक पशुपालन और मजबूत सहकारी व्यवस्था पर निरंतर काम होता रहा तो भारत न केवल दुग्ध उत्पादन में विश्व में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखेगा बल्कि वैश्विक डेयरी उत्पाद निर्यात में भी नई पहचान स्थापित करेगा। बिहार जैसे राज्यों की नई पहल इस दिशा में देश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित हो सकती है।

लेखक – कांतिलाल मांडोत

जंतर-मंतर के छात्र आंदोलन की सरकार के वादा खिलाफी से छात्र असंतुष्ठ हैं ?

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां असहमति व्यक्त करने का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। जब समाज का कोई वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर संगठित होकर आवाज उठाता है, तो उसे लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। हाल के दिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों द्वारा किया गया आंदोलन और 20 जुलाई 2026 के संसद चलो कार्यक्रम ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हजारों युवाओं की भागीदारी ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या आज का छात्र पहले की तुलना में अधिक निर्भीक होकर सरकार के सामने अपनी बात रख रहा है। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी, सरकार के विरुद्ध लगाए गए तीखे नारे और पुलिस के साथ हुए टकराव ने इस बहस को और गहरा कर दिया।

इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें केवल किसी एक विश्वविद्यालय या राज्य के छात्र नहीं थे, बल्कि विभिन्न राज्यों के युवा एक साझा मुद्दे पर एक मंच पर दिखाई दिए। जब किसी आंदोलन का आधार व्यापक जनहित का प्रश्न बन जाता है, तब उसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी होता है। यही कारण है कि जंतर-मंतर का यह आंदोलन सामान्य छात्र प्रदर्शनों से अलग दिखाई दिया।

कई विश्लेषकों का मानना है कि इस आंदोलन ने यह संकेत दिया कि नई पीढ़ी केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह आवश्यकता पड़ने पर सड़क पर उतरकर भी अपनी बात कहने को तैयार है। यदि यह आकलन सही है, तो यह लोकतांत्रिक भागीदारी का संकेत हो सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक आंदोलन के आधार पर पूरे छात्र समुदाय की मनःस्थिति के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

भारतीय छात्र आंदोलनों का इतिहास बताता है कि जब भी युवाओं ने किसी मुद्दे को अपने भविष्य से जोड़ा है, तब उनकी भागीदारी व्यापक हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक, छात्रों ने सत्ता से प्रश्न पूछने का साहस दिखाया। वर्तमान आंदोलन भी इसी परंपरा की याद दिलाता है, हालांकि इसकी परिस्थितियां अलग हैं।

इस आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना खुलकर हुई। कई प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। यह दृश्य उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जो मानते हैं कि आज का युवा राजनीतिक रूप से उदासीन हो गया है। इसके विपरीत, आंदोलन ने यह संकेत दिया कि जब भविष्य और अवसरों का प्रश्न सामने आता है, तब छात्र खुलकर अपनी राय रखते हैं।

हालांकि यह कहना कि "सरकार का डर पूरी तरह खत्म हो गया है, एक व्यापक निष्कर्ष होगा, जिसके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। किसी आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी यह अवश्य दिखाती है कि अनेक छात्र सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सभी छात्रों के मन से भय समाप्त हो गया है। अलग-अलग क्षेत्रों, संस्थानों और परिस्थितियों में छात्रों के अनुभव भिन्न हो सकते हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और उसके बाद की घटनाओं पर भी व्यापक चर्चा हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगाए, वहीं प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन घटनाओं के बाद कुछ मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग भी की गई।

लोकतंत्र में किसी भी सरकार की आलोचना करना नागरिक का अधिकार है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि विरोध शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में रहे। इसी प्रकार राज्य की जिम्मेदारी है कि वह शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखे। यही संतुलन लोकतंत्र की परिपक्वता का आधार है।

इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी रहा कि परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हुई। व्यापक जनदबाव के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधारों की घोषणा की, एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित की और संबंधित विधायी कदम भी उठाए। इससे यह संकेत मिलता है कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का नीति-निर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है।

आज का छात्र पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और सूचना तक आसान पहुंच ने उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सचेत बनाया है। यही कारण है कि वह केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की भी कोशिश करता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए सकारात्मक हो सकती है, यदि इसे संवाद और संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ाया जाए।

जंतर-मंतर का आंदोलन यह अवश्य दशार्ता है कि भारतीय छात्र समुदाय का एक महत्वपूर्ण वर्ग अपनी बात खुलकर रखने को तैयार है। लेकिन यह कहना कि "सरकार का डर पूरी तरह समाप्त हो गया है", उपलब्ध तथ्यों से स्थापित निष्कर्ष नहीं है। अधिक संतुलित निष्कर्ष यह होगा कि इस आंदोलन ने अनेक छात्रों में अपनी मांगों को सार्वजनिक रूप से उठाने का आत्मविश्वास प्रदर्शित किया और सरकार तथा समाज दोनों को यह संदेश दिया कि युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुनना आवश्यक है। लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि सरकारें आलोचना सुनें, नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें और संवाद के माध्यम से समाधान खोजे जाएं।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

धरती तप रही है : बढ़ती गर्मी और मानव जीवन पर मंडराता खतरा

आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। वास्तव में, कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि आज पूरी मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और कार्बन उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में हीटवेव, सूखा, बाढ़, अनियमित वर्षा, समुद्र-स्तर में वृद्धि और जंगलों में भीषण आग जैसी घटनाओं के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

बढ़ती गर्मी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों, श्रमिकों तथा गरीब और विकासशील देशों की आबादी पर पड़ रहा है इसी संदर्भ में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (इपीआइसी) के अंतर्गत कार्यरत क्लाइमेट इंपेक्ट लैब ने मार्च 2026 में अडैप्टेशन रोडमैप : ह्यूमन हेल्थ-बढ़ते तापमान का मौत पर असर मापना ताकि अडैप्टेशन प्लानिंग को टारगेट किया जा सके शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण होने वाली ताप-जनित (हीट-रिलेटेड) मौतों तथा उनसे बचाव के उपायों का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार यदि वैश्विक तापमान वर्तमान गति से बढ़ता रहा, तो अत्यधिक गर्मी के कारण हर वर्ष लगभग 4.3 लाख (430,000) अतिरिक्त लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब देशों पर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जलवायु अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए आवश्यक संसाधन सीमित हैं। रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि मृत्यु दर केवल तापमान बढ़ने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोगों को विश्वसनीय बिजली, एयर कंडीशनर, शीतल आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रभावी हीट-एक्शन प्लान जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं। दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका को सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक गर्मी के साथ गरीबी और ऊर्जा की कमी भी मौजूद है। बढ़ते तापमान का एक और गंभीर परिणाम जंगलों में लगने वाली आग की बढ़ती घटनाएँ हैं। इससे न केवल जैव-विविधता और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है, बल्कि मानव बस्तियाँ भी खतरे में आ जाती हैं। यूरोप, जिसे कभी अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र माना जाता था, अब वहाँ भी वनाग्नि की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के जंगल हाल के वर्षों में भीषण आग से प्रभावित हुए, जिसके कारण लगभग ढाई लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। भारत में भी हर वर्ष जंगलों की आग से वन संपदा, वन्यजीवों और पर्यावरण को व्यापक क्षति होती है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यदि अभी से स्वच्छ ऊर्जा, विश्वसनीय बिजली, किफायती शीतलन (कूलिंग) सुविधाओं, प्रभावी हीट-एक्शन प्लान, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना में निवेश किया जाए, तो वर्ष 2050 तक होने वाली लाखों संभावित मौतों को रोका जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर संकट बन चुका है। इसलिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा को बढ़ावा, वनों का संरक्षण और प्रभावी जलवायु अनुकूलन उपाय अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व स्तर पर अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। विडंबना यह है कि जिन देशों का कार्बन उत्सर्जन में योगदान सबसे कम है, वही जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। दूसरी ओर, विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या तथा बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कार्बन उत्सर्जन को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसमें विकसित देशों का योगदान सबसे अधिक है, फिर भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में उनकी अपेक्षित सक्रियता दिखाई नहीं देती।

अंततः निष्कर्ष के तौर पर यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक तापमान को कम करना केवल सरकारों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर सौर, पवन और जल जैसी हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी तथा उद्योगों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और जन-जागरूकता को भी बढ़ावा देना होगा। यदि आज ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को और भी गंभीर जलवायु संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग अपनाकर ही पृथ्वी को सुरक्षित, स्वच्छ और रहने योग्य बनाया जा सकता है।

लेखक- सुनील कुमार महला
(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार।)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

बाल विवाह

बदलती सोच के बावजूद चुनौती बरकरार है

बिहार के ग्रामीण इलाकों में पिछले एक दशक के दौरान बाल विवाह को लेकर तस्वीर बदली जरूर है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी अनेक गांवों में ऐसी लड़कियां हैं, जिनकी उम्र किताबों, खेल के मैदान, सपनों और आत्मनिर्भर बनने की होती है, लेकिन उनके हाथों में स्कूल बैग की जगह विवाह की जिम्मेदारियां थमा दी जाती हैं। यह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि ऐसा फैसला है जो एक लड़की के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, आत्मविश्वास और भविष्य की संभावनाओं को एक साथ प्रभावित करता है।

किसी लड़की का जीवन केवल उसकी उम्र से तय नहीं होता, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ, जाति, शिक्षा, रहने का स्थान और उपलब्ध अवसर भी उसके भविष्य को आकार देते हैं। यही कारण है कि बाल विवाह का असर हर लड़की पर एक जैसा नहीं पड़ता। जो लड़की पहले से ही गरीबी, सामाजिक भेदभाव और सीमित संसाधनों के बीच जीवन जी रही होती है, उसके लिए बाल विवाह अवसरों के लगभग सभी दरवाजे एक साथ बंद कर देता है।

हालांकि पिछले दस वर्षों में बिहार में बाल विवाह की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। जो बदलाव गांवों में दिखाई देता है, वह आंकड़ों में भी दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ठऋक्ष्ळ्र-4, 2015-16) के अनुसार बिहार में 20 से 24 वर्ष की आयु की 39.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो चुका था। वहीं 2019-21 में यह आंकड़ा घटकर 29.9 प्रतिशत रह गया। यानी लगभग 9 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई। यह बदलाव उम्मीद जगाता है, लेकिन यह भी सच है कि बिहार अब भी उन राज्यों में शामिल है जहाँ बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

बिहार में बाल विवाह की दर में आई कमी के पीछे कुछ कारण भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों की शिक्षा पर बढ़ता जोर, विद्यालयों तक बेहतर पहुंच, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, किशोरी समूहों की सक्रियता, स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान, पंचायतों की भागीदारी और बाल विवाह निषेध कानून के बारे में बढ़ती जानकारी ने समाज की सोच को धीरे-धीरे बदलना शुरू किया है। कई गैर-सरकारी संगठनों ने भी गांवों में किशोरियों और उनके अभिभावकों के साथ लगातार संवाद कर यह समझाने का प्रयास किया कि जल्दी विवाह किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरूआत है।

ग्रामीण बिहार में अब पहले की तुलना में माता-पिता की सोच भी बदल रही है। पहले जहां बेटी की शादी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता था, वहीं अब धीरे-धीरे उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। अनेक परिवार अब अपनी बेटियों को इंटरमीडिएट, स्नातक और व्यावसायिक शिक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं।

इसके अलावा सरकारी नौकरियों, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं, स्वयं सहायता समूहों और निजी क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने भी इस सोच को और मजबूत किया है। यही कारण है कि कई परिवार अब लड़कियों की शादी 20 वर्ष या उससे अधिक आयु में करने को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके।

लेकिन यह बदलाव हर गांव, और हर परिवार तक एक जैसा नहीं पहुंचा है। जिन परिवारों पर गरीबी, सामाजिक भेदभाव और संसाधनों की कमी का दबाव सबसे अधिक है, वहां बाल विवाह का खतरा आज भी ज्यादा दिखाई देता है। ठऋक्ष्ळ्र-5 के आंकड़े भी बताते हैं कि बाल विवाह की दर सबसे अधिक आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों, कम शिक्षित अभिभावकों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों में देखने को मिलती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में बाल विवाह का प्रतिशत अन्य समुदायों की तुलना में अधिक है। वहीं अन्य समुदायों की बात करें तो इनमें कम आय वर्ग वाले परिवारों में बाल विवाह का जोखिम सबसे अधिक पाया गया है।

इसके पीछे केवल परंपरा जिम्मेदार नहीं है। गरीबी, शिक्षा की कमी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, घर से स्कूल की दूरी, रोजगार के सीमित अवसर, दहेज का डर, सामाजिक दबाव और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बनी आशंकाएं भी परिवारों को जल्दी विवाह की ओर धकेलती हैं। कई गांवों में आज भी यह धारणा मौजूद है कि बेटी जितनी जल्दी विवाह कर लेगी, परिवार उतना सुरक्षित रहेगा। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि असमान विकास, गरीबी और अवसरों की कमी का भी परिणाम है।

बाल विवाह का असर शादी वाले दिन से नहीं, उसके बाद के पूरे जीवन में दिखाई देता है। सबसे पहले पढ़ाई छूटती है। फिर रोजगार के अवसर कम होते जाते हैं। धीरे-धीरे आर्थिक आत्मनिर्भरता, फैसले लेने की आजादी और अपने लिए सपने देखने की गुंजाइश भी सिमटने लगती है। इसका दूसरा गंभीर प्रभाव लड़की के स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। कम उम्र में गर्भधारण का खतरा भी बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार इससे मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशुओं दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन इसका असर केवल शरीर पर नहीं पड़ता। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। बचपन से सीधे वयस्क जिम्मेदारियों में प्रवेश करने वाली लड़कियां अक्सर तनाव, अकेलेपन और अपनी इच्छाओं को दबाकर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

इन सबके बावजूद बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से बाल विवाह के खिलाफ उठने वाली आवाजें और बदलाव की कई प्रेरक कहानियां भी सामने आ रही हैं। अनेक पंचायतों में मुखिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जीविका समूह, शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर बाल विवाह रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई गांवों में किशोरी समूह स्वयं ऐसी शादियों की सूचना प्रशासन तक पहुंचा रही हैं। यह बदलाव बताता है कि जब समुदाय, प्रशासन और परिवार एक साथ खड़े होते हैं, तब वर्षों पुरानी सामाजिक मान्यताओं को भी बदला जा सकता है।

हम आजादी के 79वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं. विकसित भारत का सपना देख रहे हैं. दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं. हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर गर्व कर रहे हैं। लेकिन इसी देश के अनेक ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी लड़कियां हैं, जिनका बचपन उनकी इच्छा से पहले विवाह की जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ढ़ेरों उपलब्धियों के बावजूद हम बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को अब तक पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं कर पाए हैं?

दिव्या कुमारी
सीतामढ़ी, बिहार

संक्षिप्त वार्ता

डीयू कार्यकारी परिषद ने विरोध के बीच सेमेस्टर अवे प्रोग्राम और सीधे पीएचडी प्रवेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद ने बृहस्पतिवार को विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर स्नातक छात्रों के लिए ह्यसेमेस्टर अवे प्रोग्राम शुरू करने को मंजूरी दे दी। साथ ही, परिषद ने चार साल के स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रम से सीधे पीएचडी में दाखिले को भी मंजूरी दे दी।

ये फैसले ऐसे समय में लिए गए, जब परिषद के निर्वाचित सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर चिंता जताई और आशंका व्यक्त की कि इससे विश्वविद्यालय की डिग्रियों की गरिमा और मान्यता कमजोर हो सकती है। ये फैसले कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में लिए गए। स्नातक पाठ्यचर्या रूपरेखा (यूजीसीएफ)-2022 के तहत प्रस्तावित सेमेस्टर अवे प्रोग्राम (एसएपी) पर विश्वविद्यालय पहले भी विचार कर चुका था और इस पर शैक्षणिक परिषद में भी चर्चा हुई थी।

संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा मनाएगी सात माह लंबा उत्सव

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। संत रविदास की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देशभर में सात माह लंबे उत्सव का आयोजन करने जा रही है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली पर आयोजित कार्यक्रम में देशभर से पहुंचे भाजपा के प्रदेश संगठनों को उनकी जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी से भरे कलश सौंपे। इन कलशों को संबंधित राज्यों के गांव-गांव और गली-गली तक ले जाया जाएगा।

दिल्ली भाजपा की 11 सदस्यीय टीम भी संत रविदास की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी का कलश लेकर शुक्रवार को दिल्ली पहुंची। दिल्ली-नोएडा सीमा पर दिल्ली सरकार के मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, दिल्ली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाजपत राय, विधायक राजकुमार भाटिया एवं रविकांत, दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष विनोद बछेती एवं कौशल शर्मा, मंत्री गौरव खारी, प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी, कार्यालय मंत्री कैलाश जैन, मयूर विहार जिलाध्यक्ष विजेन्द्र धामा और शाहदरा जिलाध्यक्ष दीपक गाबा सहित अन्य नेताओं ने 11 सदस्यीय टीम का स्वागत किया।

रुचिका सिंह के समर्थन में उतरी सीजेपी, प्राथमिकी को बताया अनुचित

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि इस मामले में आपराधिक प्रावधानों का उपयोग उचित नहीं है और युवाओं को अनावश्यक रूप से परेशान करना बंद किया जाना चाहिए।

सौरव दास ने सामाजिक माध्यम पर जारी अपने वक्तव्य में कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रयुक्त भाषा की आलोचना की जा सकती है, लेकिन केवल इसी आधार पर आपराधिक कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई के बजाय अभिव्यक्ति की प्रकृति और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि देश की संसद में बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जिनके विरुद्ध विभिन्न आपराधिक मामले लंबित हैं। उनका कहना था कि पुलिस को अपनी ऊर्जा गंभीर आरोपों वाले मामलों पर केंद्रित करनी चाहिए, न कि एक युवा महिला के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई में।

मकोका आरोपों के खिलाफ सुकेश की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। 200 करोड़ रुपए कीवसूली और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुकेश ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए मकोका के आरोपों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।

राजधानी में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर घटी वाहनों की गति सीमा

कार के लिए गति सीमा 100 से कम कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गई

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम कर दी गई है। अब कार अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेगी। वहीं ट्रक, बस समेत सभी भारी वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा सीमित कर दी गई है। दुर्घटना की आशंका को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एक्सप्रेसवे पर लगे स्पीड रडार में नई गति सीमा को अपडेट कर दिया गया है। अब पुरानी गति सीमा पर वाहन दौड़े तो चालान कट जाएगा।

दिल्ली की सीमा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर लोनी बॉर्डर तक 14.75 किलोमीटर लंबा है। इसी वर्ष 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। तब राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में गांधी नगर से लोनी बॉर्डर तक इसके 6.5 किलोमीटर के एलिवेटेड खंड पर धीमी गति के वाहनों में शामिल दोपहिया वाहन और ई-रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बाकी वाहनों की गति सीमा को लेकर सुझाव मांगा था। उस वक्त इस पर निर्णय नहीं होने के कारण एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे पर उसकी डिजाइन स्पीड के अनुसार वाहनों का परिचालन लागू किया गया था। कार के लिए 100 और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा रखी गई थी। शास्त्री पार्क के पास तीव्र मोड़ वाले स्थानों पर गति सीमा 85 और 65 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी।

अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एनएचएआई को इस एक्सप्रेसवे पर कार के लिए गति सीमा घटाकर 70 और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा करने की संस्तुति की है। एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि इस संस्तुति को मानते हुए नई गति सीमा लागू करने के साथ एक्सप्रेसवे पर लगे बोर्डों पर नई गति सीमा लिखवाने का काम शुरू कर दिया है।

मास्टर प्लान और कॉलोनियों के मुद्दों पर खट्टर से मिले रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मास्टर प्लान, ओ-जोन, एफ्लुएंट कॉलोनियों के नियमितीकरण तथा अन्य शहरी विकास संबंधी विषयों को लेकर केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक में विभिन्न लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग रखी गई।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 92 कॉलोनियों और एक दर्जन प्राचीन गांवों को ओ-जोन से बाहर कर नियमित की जा रही 1511 कॉलोनियों में शामिल करने तथा 69 एफ्लुएंट कॉलोनियों के नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने विभाजन के समय दिल्ली आए परिवारों की लीज समाप्त हो चुकी कॉलोनियों को फ्रीहोल्ड करने का भी आग्रह किया।

बैठक में लैंड पूलिंग नीति में तेजी लाने, जीडीए नीति लागू करने, अधिक व्यावसायिक गतिविधियों वाली सड़कों को व्यावसायिक घोषित करने, सील पड़ी दुकानों को खोलने, गांवों की विस्तारित आबादी को नियमित करने तथा भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों के सर्किल रेट बढ़ाने जैसे विषय भी उठाए गए। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि मनोहर लाल खट्टर ने इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार इनके समाधान के लिए कार्ययोजना पर विचार कर रही है।

सामान्य से अधिक बारिश के बावजूद दिल्ली में सात साल में सबसे प्रदूषित जुलाई दर्ज

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली में जुलाई का महीना मौसम के उतार-चढ़ाव वाला रहा। एक तरफ जहां लगभग 10 साल में पहली बार हवा की गुणवत्ता अच्छी रही, वहीं दूसरी ओर पिछले सात साल में जुलाई का महीना सबसे अधिक प्रदूषित भी रहा। लंबे समय तक शुष्क मौसम के बाद कुछ तेज बारिश के कारण मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक रही, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में सात वर्षों का सबसे प्रदूषित जुलाई दर्ज किया गया।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के विश्लेषण के अनुसार, जुलाई के पहले 30 दिन में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 119 रहा। यह 2019 के बाद जुलाई महीने का सबसे अधिक औसत है, जब एक्यूआई 134 दर्ज किया गया था। यह औसत पिछले साल जुलाई महीने के 78 के औसत से काफी अधिक था।

मासिक औसत भले खराब रहा हो, लेकिन दिल्ली में नौ साल में पहली बार जुलाई में हवा की गुणवत्ता अच्छी रही और एक्यूआई गिरकर 48 पर आ गया। यह जुलाई में दर्ज किया गया सबसे कम दैनिक न्यूनतम एक्यूआई था। इससे पहले 2017 में यह 43 तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ, जुलाई के महीने के दौरान एक्यूआई बढ़कर 261 हो गया जो जुलाई में पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक दैनिक अधिकतम एक्यूआई था। इससे पहले 2021 में यह 266 था।

महीने के दौरान, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 15 दिन मध्यम, 12 दिन संतोषजनक, दो दिन खराब और एक दिन अच्छी रही, जबकि एक भी दिन हवा की गुणवत्ता बहुत खराब नहीं दर्ज की गई। सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम 201 से 300 के बीच खराब 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मानसून की गतिविधि में लंबे समय तक रुकावट के बावजूद, अधिकतर मौसम केंद्रों पर इस महीने बारिश सामान्य से अधिक रही।

'विद्या वाहिनी' योजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को वितरित कीं निःशुल्क साइकिलें

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'विद्या वाहिनी' योजना का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत 3,000 से अधिक छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं से आत्मीय संवाद किया, उनकी पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और सपनों के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की प्रतिभा और स्नेह की सराहना करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम नारी शक्ति के सम्मान और प्रत्येक बेटी को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण में महिला-नेतृत्व वाले विकास को केंद्र में रखा है तथा शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम माना है। 'विद्या वाहिनी' योजना उसी दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विद्या वाहिनी' योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार के विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1 .40 लाख छात्राओं को नि :शुल्क साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी और यह योजना आगे के वर्षों में भी इसी तरह जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह योजना छात्राओं के विद्यालय तक सुरक्षित एवं सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेगी, उनके समय की बचत करेगी, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति बढ़ाएगी, ड्रॉपआउट की संभावना को कम करेगी तथा अभिभावकों की दैनिक चिंता को भी कम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं होती, बल्कि यह स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, गरिमा, आत्मनिर्भरता और अवसर का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त करती, बल्कि आत्मविश्वास, जागरूकता और अपने भविष्य से जुड़े सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती है।

छात्र आंदोलन के दौरान पत्थरों से भरा ट्रक कहां से आया, इसकी हो व्यापक जांच : युवा कांग्रेस

नई दिल्ली, वेब वार्ता

युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर, संसद मार्ग और बाद में युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में पत्थरों से भरा एक ट्रक आया, जिसे लेकर यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि ट्रक कहां से, कैसे, किसके निर्देश पर और किस उद्देश्य से लाया गया था। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में इस पूरे मामले की व्यापक स्तर पर न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने 20 जुलाई को अपराह्न करीब पौने चार बजे युवा कांग्रेस कार्यालय के सामने पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा देखा था। उस समय वहां करीब 500 छात्र मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि दोपहर करीब 12 बजे संसद मार्च शुरू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे छात्र और युवा तितर-बितर हो गए लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोग ट्रक पर चढ़े हुए थे, जिन्हें पुलिस ने नहीं रोका। उन्होंने कहा कि यह वही ट्रक था, जिसका 16 जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद संसद मार्ग थाने में पुलिस की अभिरक्षा में होने का दावा किया गया था। इसके बावजूद 20 जुलाई को वही ट्रक जंतर-मंतर, संसद मार्ग और बाद में युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर पत्थरों और अन्य वस्तुओं से भरा खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने सवाल किया कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग के बीच यह ट्रक संसद मार्ग तक कैसे पहुंचा, इसे कौन चला रहा था और पुलिस की अभिरक्षा में होने के बावजूद इसे कई दिनों तक सड़कों पर किसके आदेश पर रखा गया।

श्री चिब ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में इस ट्रक को प्रदर्शनकारियों से जोड़ने का प्रयास किया गया, जबकि 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर कहा कि यह ट्रक एक दुर्घटना के बाद जब्त किया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों दावों में स्पष्ट विरोधाभास है और इससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि संसद से करीब 100 मीटर की दूरी पर पत्थरों और अन्य वस्तुओं से भरे ट्रक को बिना निगरानी के छोड़ना एक बड़ी सुरक्षा चूक है। उन्होंने सवाल किया कि यदि असामाजिक तत्व इन पत्थरों का इस्तेमाल कर हिंसा फैलाते, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती।

उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी युवा कॉंग्रेस

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर विपक्ष के युवा संगठन के कार्यालय के बाहर यह ट्रक खड़ा किया, तो इसकी मंशा स्पष्ट की जानी चाहिए। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र एवं न्यायिक जांच कराने, ट्रक की आवाजाही से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, पूरे घटनाक्रम की ह्यचेन ऑफ कमांडह्ल सार्वजनिक करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और युवा कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।

यौन प्रताड़ना मामले में डीयू के शिक्षक को जबरन सेवानिवृत्ति

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यौन प्रताड़ना के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर अमल करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के एक शिक्षक को जबरन सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है। यह निर्णय गुरुवार को हुई विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में लिया गया।

कार्यकारी परिषद की बैठक में मौजूद एक सदस्य के अनुसार, संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभाग की एक शोधार्थी ने यौन प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने की। जांच के बाद समिति ने शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश करते हुए उन्हें सेवा से हटाने की अनुशंसा की थी। इसी सिफारिश के आधार पर कार्यकारी परिषद ने शिक्षक को जबरन सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने आरोपी शिक्षक के पक्ष में अपनी बात रखी, लेकिन कुलपति सहित अधिकांश सदस्यों का मत था कि यह मामला केवल एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और संस्थान की गरिमा से जुड़ा है। इस कारण मामले में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से स्पष्ट इनकार किया गया और सख्त कार्रवाई पर सहमति बनी। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि डीयू यौन उत्पीड़न के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौते की नीति नहीं अपनाएगा और शिकायतों के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऐसे मामलों में कई कड़े फैसले लिए हैं।

जंतर-मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर संसद कूच के दौरान हुई हिंसा के आरोपितों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भेजकर दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सहित सख्त धाराओं में कार्रवाई करने की मांग उठाई।

दिल्ली दंगे: उमर खालिद की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। खालिद के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद यह उसकी तीसरी जमानत याचिका है और उसने मामले में अंतरिम जमानत का भी अनुरोध किया है। पीठ ने कहा कि वह खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। खालिद ने अधीनस्थ अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने इसी आदेश में इमाम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी इसलिए पीठ दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई कर सकती है। सितंबर 2020 में गिरफ्तार खालिद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर फरवरी 2020 के दंगों के मुख्य साजिशकताओं में शामिल होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा उस कथित व्यापक साजिश के मामले की जांच कर रही है जिसमें शरजील इमाम और खालिद सैफी तथा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अधीनस्थ अदालत ने चार जुलाई को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके पास उच्चतम न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा ह्यह्यकोई विकल्प नहींह्लह्ल है और इसलिए वह न तो याचिका पर विचार कर सकती है और न ही उन्हें राहत दे सकती है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दो सितंबर 2025 को उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी को इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सह-आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी।

पालम अग्निकांड में फेल हो गई थी फायर ब्रिगेड की स्काई लिफ्टः सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के पालम इलाके में 18 मार्च को हुए भीषण अग्निकांड मामले में दिल्ली सरकार के झूठ की पोल खुल ही गई। इस अग्निकांड में आई जिलाधिकारी (डीएम) की जांच रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर फायर विभाग की स्काई लिफ्ट फेल नहीं होती तो जान गंवाने वाले 9 लोगों में से कइयों को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि फायर विभाग की नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार और मंत्रियों ने लगातार झूठ बोलकर दिल्ली के लोगों को गुमराह किया।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही कह रही हैं कि अगर फायर ब्रिगेड के स्काई लिफ्ट फेल नहीं होते, तो पालम अग्निकांड में जान गंवाने वाले नौ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार झूठ बोल कर दमकल विभाग की नाकामियों पर पर्दा डालते रहे।

सौरभ भारद्वाज ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि डीएम की इस रिपोर्ट को आने और सार्वजनिक होने में लगभग आधा साल लग गया, जो कि वास्तव में बेहद शर्मनाक है।

संक्षिप्त वार्ता

कुशीनगर में 30 दिन में 492 सर्पदंश के मामले सामने आए

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर जिले में बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी के बीच जिले में सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कुशीनगर मेडिकल कालेज में पिछले 30 दिनों के दौरान सर्पदंश के 492 मरीज भर्ती किए गए। इसमें लापरवाही बरतने के कारण नौ की जान चली गई।

चिकित्सकों का कहना है कि झाड़-फूंक में विलंब के कारण सर्पदंश के शिकार को समय से उपचार की सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण बचाया नहीं जा सका।परिजन पहले झाड़-फूंक और घरेलू उपचार के चक्कर में समय गंवा देते हैं, जिससे मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। सर्पदंश के शिकार ठाढ़ीभार की सरिता देवी, खिरकिया के 25 वर्षीय राजा हुसैन, जंगल नाहर छपरा के 55 वर्षीय नरेश गोंड, कोटवा की सीमा देवी, रामपुर राजा के 55 वर्षीय राम नारायण को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। बुधवार को पहुंचे बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा के 22 वर्षीय सत्येंद्र सिंह की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया।

इस संबंध में कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य डा के पी गौड ने बताया कि अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में मरीजों का उपचार चल रहा है। मेडिकल कालेज में प्रतिदिन औसतन आठ से अधिक सर्पदंश पीड़ित उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। डाक्टरों का कहना है कि सर्पदंश के बाद शुरूआती एक से दो घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इमरजेंसी इंचार्ज पुष्कर पाठक ने बताया कि बीते 21 जून से 20 जुलाई तक 492 सर्पदंश के शिकार आए, जिनके उपचार में कुल 2300 एएसवी खर्च हुए।

पीएनबी ने शिक्षकों को दिया बैंक से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन

वेब वार्ता, कुशीनगर

पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में बुधवार को कसया नगर स्थित एक होटल में आयोजित संगोष्ठी में शिक्षकों को बैंक से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों एवं बैंक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा बैंकिंग सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करना रहा। बुधवार को संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर मंडल प्रमुख महेंद्र कुमार मोहन, रेखा रामचंद्रन, राजकुमार सिंह तथा अभिनाश शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद वक्ताओं ने शिक्षकों से जुड़ी बैंकिंग सुविधाओं, ऋण व्यवस्था तथा वेतन खातों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में वर्तमान समय में शिक्षकों के वेतन खाते अन्य बैंकों, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक में स्थानांतरित होने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षकों से पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े रहने की अपील करते हुए बैंक की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी।

मुख्य वक्ता प्रोटान की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रेखा रामचंद्रन ने कहा कि नौकरी के प्रारंभ से ही उनका वेतन पंजाब नेशनल बैंक में आ रहा है और उन्हें बैंक की सेवाओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं किसी अन्य बैंक में जाने के पक्ष में नहीं हैं तथा शिक्षकों से भी पीएनबी के साथ जुड़े रहने का आग्रह किया।

कानपुर आरटीओ का बड़ा एक्शन : छापेमारी से हड़कंप, भनक लगते ही दुकानें बंद कर भागे कई संचालक

अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर चला हंटर, फर्जी सेंटरों के पंजीयन होंगे निरस्त

कानपुर। शहर की सड़कों पर बिना सही ट्रेनिंग के गाड़ियाँ दौड़ाने वाले और नियमों को ताक पर रखकर दुकानें सजाने वाले अवैध मोटर ड्राइविंग सेंटरों पर संभागीय परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ की इस सख्त कार्रवाई से शहर के अवैध ड्राइविंग स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

संभागीय परिवहन विभाग के प्रावधिक मोटर यान निरीक्षक (आआई) संतोष कुमार ने बीते दो दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान यह चैंकाने वाला खुलासा हुआ कि कानपुर नगर में केवल 10 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ही वैध एवं अधिकृत हैं, जबकि बाकी सेंटर पूरी तरह से अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं।

आरआई संतोष कुमार द्वारा की गई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं और फजीर्वाड़े सामने आए है। कई ड्राइविंग स्कूल ऐसे मिले जिनका कागजों में पंजीकृत पता कुछ और था, जबकि वे किसी दूसरे ही इलाके में अवैध रूप से सेंटर चला रहे थे। जांच में कैनाल रोड स्थित परफेक्ट मोटर ड्राइविंग स्कूल, राष्ट्रीय मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, और हिंदुस्तान मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अनाधिकृत रूप से संचालित पाए गए। आरआई के निरीक्ष्ण की भनक लगते ही रफूचक्कर हो गए। वहीं सहारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग का ट्रेनर सेंटर में ताला लगाकर मौके से भाग निकला। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी। शहर में अवैध ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले और लोगों की जान जोखिम में डालने वाले किसी भी अनाधिकृत ट्रेनिंग सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा।

मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (आनंद नगर) में जांच के दौरान एक युवक (प्रशांत) नियम दरकिनार कर निजी (प्राइवेट) वाहन से अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। नमक फैक्ट्री चैराहे पर संचालित मिश्रा मोटर ड्राइविंग स्कूल का पंजीकृत पता श्डबल पुलियाश दर्ज था। मौके पर मिले कर्मचारी राम खिलाड़ी से पूछताछ करने पर वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसी तरह फूलबाग चैराहे और पर्यटन अधिकारी कार्यालय कैंपस के आसपास फूले मोटर ड्राइविंग स्कूल के बोर्ड तो मिले, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था।

अब होगी सख्त कार्रवाई, गाड़ियां होंगी ब्लैकलिस्ट

आरआई संतोष कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी अवैध सेंटरों का ब्योरा इकट्ठा कर लिया गया है। अनाधिकृत रूप से चल रहे इन सभी ड्राइविंग स्कूलों को स्थायी रूप से बंद कराने और इनके वाहनों पर सख्त कार्रवाई के लिए उप परिवहन आयुक्त (कानपुर परिक्षेत्र) को विस्तृत जांच आख्या सौंप दी गई है। अवैध रूप से संचालित मोटर ड्राइविंग स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके पंजीयन को निरस्त करने की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।

कांवड़ यात्रा को लेकर रोडवेज की विशेष व्यवस्था

वेब वार्ता, मुरादाबाद। कांवड़ मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारु यातायात व्यवस्था और निर्बाध परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रूट डायवर्जन के अनुरूप कई बस मार्गों के किराए में संशोधन किया है। परिवर्तित मार्गों के कारण बसों को अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसके चलते नया किराया लागू किया गया है।

नई किराया सूची के अनुसार मुरादाबादझ्र दिल्ली का सामान्य बस किराया 282 रुपये से बढ़कर 317 रुपये, मुरादाबादझ्रबिजनौर का 134 रुपये से 193 रुपये, मुरादाबादझ्रदेहरादून का 376 रुपये से 443 रुपये, मुरादाबाद-हरिद्वार का 259 रुपये से 325 रुपये कर दिया गया है। वहीं मुरादाबाद-कौशांबी मार्ग पर सामान्य सेवा का किराया 250 रुपये से बढ़कर 291 रुपये तथा एसी प्रीमियम 22 जनरथ सेवा का किराया 368 रुपये से बढ़ाकर 440 रुपये निर्धारित किया गया है।

रूट डायवर्जन से कुछ मार्गों पर किराया संशोधित

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने अस्थायी रूप से बस संचालन व्यवस्था में भी बदलाव किया है। रामपुर, बरेली, दिल्ली, संभल, चंदौसी और मेरठ रूट की रोडवेज बसों का संचालन आजाद नगर से किया जाएगा। वहीं धामपुर, बिजनौर और हरिद्वार रूट की बसें प्रेम वंडरलैंड से संचालित होंगी, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात सुचारु बना रहे और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। सेवा प्रबंधक अनुराग यादव ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने निर्धारित बस प्रस्थान स्थल और संशोधित किराए की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे यात्रा सुरक्षित, सुगम और परेशानी मुक्त रहे।

एसपी संजीव कुमार बाजपेयी के कुशल नेतृत्व में महरौनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। जनपद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेयी की सख्त कार्यशैली का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में महरौनी पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का सफल खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंतरराज्यीय आरोपी सोनू धापनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी की 2 लाख 23 हजार 560 की नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, महरौनी क्षेत्र में बैंक से रुपये निकालकर जा रहे व्यक्ति के बैग से नकदी चोरी की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेयी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कई पुलिस टीमों का गठन किया। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह एवं क्षेत्राधिकारी महरौनी अरविंद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई। पुलिस को सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई, जहां आरोपी ने भागने का प्रयास किया।

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पूछताछ में आरोपी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। ललितपुर पुलिस की इस त्वरित और पेशेवर कार्रवाई से न केवल चोरी की घटना का सफल अनावरण हुआ, बल्कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास भी और मजबूत हुआ है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार हेतु एएनआरएफ योजनायें

वेब वार्ता, कानपुर

पंडित पृथी नाथ (पी.जी.) कॉलेज, कानपुर के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान के इनोवेशन काउंसिल ने 31 जुलाई 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों (एएनआरएफ) में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को सुदृढ़ बनाना का दृष्टिकोण, प्राथमिकताएं और सहायता ढांचा विषय पर एमआईसी संचालित एक विशेष सत्र का सफल आयोजन किया। प्रो. अनूप कुमार सिंह ने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार हेतु शिक्षकों तथा छात्रों को प्रोत्साहित किया। संस्थान के इनोवेशन काउंसिल (क्यूआइ) की संयोजक डॉ. कीर्ति चौहान द्वारा समन्वित यह सत्र अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (अठफक्र) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उएड) डॉ. शिवकुमार कल्याणरमन के लाइव संबोधन के माध्यम से यू-ट्यूब लाइव प्रसारण में किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, संकाय सदस्यों (फैकल्टी) और शोधार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्हें अठफक्र के दृष्टिकोण, अनुसंधान प्राथमिकताओं, वित्त पोषण (फंडिंग) के अवसरों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। इस सत्र में प्रो. सुमन सिंह, डॉ. एस. पी. श्रीवास्तव, डॉ. ललित मौर्य, डॉ. यशवीर गौतम, डॉ. ऋषभ गुप्ता और डॉ. श्रास्ती कटियार उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम के अकादमिक महत्व को और बढ़ाया। कार्यक्रम का समापन पी.पी.एन. (पी.जी.) कॉलेज में अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की एक नई प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

फर्जी दस्तावेजों के सहारे दूसरे की जमीन का कराया बैनामा, महिला समेत सात पर मुकदमा

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। तहसील महरौनी क्षेत्र के ग्राम पठा विजयपुरा में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन का फर्जी बैनामा कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन की गलत चौहद्दी दर्शाकर उस पर बनी बाउंड्रीवाल और पिलरों को भी अपना बताकर बैनामा करा दिया गया। राजस्व विभाग की जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद महरौनी पुलिस ने महिला समेत सात नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पठा विजयपुरा निवासी आशीष कुमार पुत्र बृजविहारी ने थाना महरौनी में दर्ज कराई गई तहरीर में बताया कि मौजा पठा विजयपुरा स्थित आराजी संख्या 1307, रकबा 0.082 हेक्टेयर, सिंदवाहा रोड से लगी हुई भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर उनकी बाउंड्रीवाल और पिलर बने हुए हैं तथा लंबे समय से उनका कब्जा है। आरोप है कि गांव के महेश पुत्र राजाराम और सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण ने सुनियोजित तरीके से जमीन की गलत चौहद्दी दर्शाते हुए पीड़ित की भूमि, बाउंड्रीवाल और पिलरों को अपना बताकर 14 जुलाई एवं 16 जुलाई 2026 को गांव की फूलन देवी पत्नी पुन्नी के नाम बैनामा करा दिया। उसका कहना है कि 17 जुलाई को जब उसे इस फर्जी बैनामे की जानकारी मिली तो उसने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत पर तहसीलदार के निर्देश पर लेखपाल द्वारा मौके की जांच की गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई और बैनामे में अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने स्तनपान को जन-आंदोलन बनाने का किया आह्वान

स्तनपान कराने की राष्ट्रीय दर 63.7 प्रतिशत से घटकर 55.8 प्रतिशत हुई

वेब वार्ता, कानपुर। विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, कानपुर द्वारा शुक्रवार को जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर के बाल रोग विभाग, में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, कानपुर के अध्यक्ष डॉ. जे. के. गुप्ता, सचिव डॉ. शैलेन्द्र गौतम, प्रो. डॉ. अरुण आर्य तथा डॉ. अमितेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026 की थीम (ब्रेस्टफीडिंग फॉर ए सस्टेंएबल स्टार्ट इन लाइफ स्टेज्ंय व्हॉट् वर्क) है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नवजात शिशु को जीवन की सर्वोत्तम शुरूआत प्रदान करना, माताओं को स्तनपान के लिए सक्षम बनाना तथा समाज में स्तनपान के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। इस अवसर पर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, कानपुर ने विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत 1 से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रमों की घोषणा भी की।

डॉ. जे. के. गुप्ता ने कहा कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) शिशु का पहला टीका है। यह संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। उन्होंने कहा कि जन्म के पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान प्रारम्भ करना, पहले छह माह तक केवल माँ का दूध देना तथा छह माह के बाद उचित ऊपरी आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना प्रत्येक परिवार का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों मुताबिक भारत में जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान प्रारम्भ कराने की दर 41.8 प्रतिशत से बढ़कर 50.1 प्रतिशत हुई है, जो सकारात्मक संकेत है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि छह माह तक केवल स्तनपान कराने की राष्ट्रीय दर 63.7 प्रतिशत से घटकर 55.8 प्रतिशत हो गई है। उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ यह दर 59.7 प्रतिशत से घटकर मात्र 34.6 प्रतिशत रह गई है। इसका अर्थ है कि प्रदेश के लगभग दो-तिहाई शिशु जीवन के पहले छह माह तक केवल माँ का दूध प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि माँ का दूध केवल पोषण ही नहीं बल्कि शिशु के मस्तिष्क के विकास, बेहतर बुद्धिलब्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा भविष्य में मोटापा, मधुमेह, एलर्जी, अस्थमा और अनेक दीर्घकालिक रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि केवल स्तनपान कराने से अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम (एसआईडीएस) का जोखिम लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो सकता है।

पिंड पात्र लेकर निकले बौद्ध भिक्षुओं को उपासकों ने दिया दान

ममता तिवारी। कुशीनगर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध का दर्शन पूजन कर कल्याण की कामना की। उपासकों ने भिक्षुओं को पिंड पात्र में फल, खाद्य सामग्री दान किया। भिक्षु डॉ कितिफान के निर्देशन में थाई भिक्षु, भिक्षु संघ कुशीनगर से जुड़े भिक्षुओं ने बुधवार की सुबह मुख्य मंदिर में धम्म पाठ कर पूजन किया और चीवर चढ़ाया। भिक्षु ने कहा कि आषाढी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बाद भिक्षु नंदका, पी पविन, भिक्षुओं ने पिंड पात्र लेकर भिक्षाटन किया। जहां उपासक टीके राय, गोपाल मद्धेशिया, धर्मेंद्र गुप्ता, सुरेश गुप्ता, राजा चौरसिया, सोहन, आशीष बरुआ, डॉ सिद्दकी, राजा चौरसिया, टेनी विश्वकर्मा, अभिषेक गोंड, मनोज प्रजापति, हिमांशु पाण्डेय, अमोद कुमार सिंह, फूल बदन बौद्ध, अमिताभ शुक्ला, चंद्र प्रकाश शर्मा, गुड्डू गुप्ता, आनंद यादव, आदित्य कुशवाहा सहित थाई भिक्षुणियों ने भी खाद्य, फल आदि भेंट किया।

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की कलश बंधन यात्रा का बलरामपुर में भव्य स्वागत

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर वाराणसी से निकली पावन कलश बंधन यात्रा का बलरामपुर जनपद की सीमा पर भव्य एवं श्रद्धापूर्ण स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल रथ एवं पवित्र कलश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के चित्र एवं कलश का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया तथा उनके बताए समरसता, समानता, प्रेम, सेवा और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पूरे वातावरण में गुरु रविदास महाराज के जयघोष एवं भक्ति गीतों से श्रद्धामय माहौल बना रहा।

स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र, सदर विधायक

पल्टूराम, विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, विधायक राम प्रताप वर्मा, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू', ब्लॉक प्रमुख राकेश तिवारी, गोविंद सोनकर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष वंदनापासवान, बृजेन्द्रतिवारी, संजय शुक्ल, वरुण सिंह 'मोनू', कार्यक्रम संयोजक शिव प्रसाद यादव, सहसंयोजक राजाराम गौतम, बिन्दू विश्वकर्मा, जिला महामंत्री डॉ.अजय सिंह 'पिंकू', महेन्द्र पाण्डेय, डीपी सिंह बैस, साधना पाण्डेय, सुधा पाण्डेय, सरोज तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकताओं एवं श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर यात्रा का भव्य स्वागत किया।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन और विचारों से समाज को समरसता, सामाजिक समानता और मानव कल्याण का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को एकजुट करने और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने की प्रेरणा देती हैं। उनकी 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही यह कलश बंधन यात्रा समाज में एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है।

देवरिया में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर पथराव, तनाव बढ़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

देवरिया 30 जुलाई। देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र में लबकनी गांव में नवीन परती की भूमि पर बिना प्रशासनिक अनुमति डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने का विवाद गुरुवार को उग्र हो गया। प्रतिमा हटाने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते ईंट-पत्थर चलने लगे। इससे गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया।

अधिकाधिक प्रवक्ता के अनुसार जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गांव लबकनी में आंगनबाड़ी केंद्र के समीप मंगलवार रात कुछ लोगों ने नवीन परती की भूमि पर प्रतिमा स्थापित कर दी थी। बुधवार सुबह मामले की जानकारी प्रशासन को हुई तो अधिकारियों में हलचल मच गई जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर रुद्रपुर के एसडीएम राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम गांव पहुंची तथा मौके की स्थिति का जायजा लिया प्रतिमा हटाए जाने की आशंका में बुधवार देर रात तक महिलाएं स्थल पर डटी रहीं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और गांव में निगरानी बढ़ा दी। इसके बावजूद गुरुवार को प्रतिमा हटाने को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद पथराव होने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। गांव में किसी तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।

महत्वपूर्ण ख़बर

पेपर लीक पर नया कानून और सख्तः परीक्षा माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी

- नई दिल्ली। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा से पारित कराया है। यह विधेयक 2024 के एंटी-पेपर लीक कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि नए प्रावधान परीक्षा माफिया पर कड़ी कार्रवाई, समयबद्ध जांच और दोषियों को शीघ्र सजा सुनिश्चित करने वाले है। जिससे सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल होगा।

राफेल को फेल बताने वाला पायलट, चीन के लिए जासूसी में धराया

- पेरिस। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान को लेकर विवादित बयान देने वाले पूर्व फ्रांसीसी नौसेना पायलट पियरे हेनरी चूएट अब गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। फ्रांस में उन्हें चीन के लिए कथित जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने और संवेदनशील सैन्य सूचनाएं लीक करने के आरोपों में हिरासत में लिया गया है। पेरिस में जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच में आरोप लगाया गया है कि पियरे हेनरी चूएट ने विदेशी ताकत के साथ खुफिया जानकारी साझा की और फ्रांस की सुरक्षा से जुड़े गोपनीय तथ्यों का खुलासा किया। उनके चीन से कथित संबंधों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला फ्रांस की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा जासूसी प्रकरण साबित हो सकता है।

ट्रंप ने रोका एक और युद्ध? दूसरी सत्ता को दी प्रशासन की कमान

अमेरिका। गाजा पट्टी में जल्द शांति की उम्मीद जागी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा में हमास और दूसरे हथियारबंद संगठनों को पूरी तरह हथियार छोड़ने (निरस्त्रीकरण) पर सहमति बन गई है. ट्रंप के मुताबिक, जैसे-जैसे इस समझौते पर अमल होगा, इजरायली सेना भी गाजा से चरणबद्ध तरीके से अपनी वापसी शुरू करेगी.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को हुए इस समझौते को शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि इस समझौते को एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जैसे ही हमास और अन्य हथियारबंद समूह पूरी तरह हथियार छोड़ देंगे.

क्या करेगी इजरायली सेना?

ट्रंप ने कहा कि इजरायली सेना गाजा से धीरे-धीरे वापस लौटना शुरू कर देगी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल और नया फिलिस्तीनी पुलिस बल मिलकर गाजा में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे, ताकि वहां रहने वाले लोगों और पड़ोसी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. हालांकि अभी तक इस पर इजरायली सेना की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी प्रशासन

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गाजा के लिए उनकी 20 सूत्रीय योजना को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर गाजा का प्रशासन एक नई फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी, जो शांति बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी. ट्रंप के मुताबिक, इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों की मदद करना और क्षेत्र में स्थायी शांति कायम करना है. वर्तमान की बात करें तो गाजा में अब हमास ने अपना प्रशासनिक ढांचा भंग कर दिया है और सत्ता राष्ट्रीय गाजा प्रशासन समिति नामक एक गैर-राजनीतिक 'टेक्नोक्रैट' समिति को सौंपी जा रही है.

इन देशों का ट्रंप ने जताया आभार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिस्र, कतर और तुर्की ने इस समझौते को कराने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने इन तीनों देशों और अपनी सरकार की टीम का धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के प्रयासों से यह बड़ी सफलता हासिल हुई है. ट्रंप ने कहा कि एक साल पहले गाजा में भीषण युद्ध चल रहा था, वहां गंभीर मानवीय संकट था और कई बंधकों को कैद करके रखा गया था. अब हमने शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है.

कैसे तैयार हुआ हमास?

यह युद्धविराम का मसौदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा योजना के तहत हुई बातचीत के बाद तैयार किया गया. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी ट्रंप की अध्यक्षता में बने शांति बोर्ड ने की. हमास के नेता पिछले सप्ताह के अंत से मिस्र की राजधानी काहिरा में मौजूद हैं, जहां वे मिस्र, कतर और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. इससे पहले अल जजीरा न्यूज एजेंसी ने हमास के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया था कि बातचीत सकारात्मक रही है और समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है. हमास ने इससे पहले 6 जुलाई को गाजा में लगभग दो दशकों तक सत्ता में रहने के बाद अपनी शासी निकाय को भंग करने की घोषणा की थी.

कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइ का खतरा!

मूसलाधार बारिश ने मचाई आफत

21 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। देश के हर राज्य में मानसून एक्टिव हो गया है, जिस वजह से विभिन्न राज्यों में भारी बारिश हो रही है. बारिश ने कई राज्यों में हाहाकार मचा दिया है, जिस वजह से कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं. इस बीच, मौसम विभाग ने 21 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की भी आशंका जाहिर की है.

मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य भारत में मानसून के अधिक सतर्क रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने समुद्री तटों के आसपास रहेन वाले लोगों और मछुआरों के लिए सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ आने की आशंका है.

अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला

कुवैत में वर ड्रोन हैंगर और फ्यूल सेंटर पूरी तरह तबाह

कुवैत। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा युद्ध शुरू हो चुका है. अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया. इसमें हमले में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ. कुवैत में अमेरिका के दो ड्रोन हैंगर और सैन्य विमानों के लिए बना फ्यूल सेंटर पूरी तरह नष्ट हो गया.

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया है. ईरान का दावा है कि इस हमले में एयरबेस के दो ड्रोन हैंगर पूरी तरह तबाह हो गए. इसके अलावा, सैन्य विमानों और

हेलीकॉप्टरों के लिए रखा गया ईंधन भंडारण केंद्र (फ्यूल सेंटर) भी नष्ट कर दिया गया.

आईआरजीसी ने शुक्रवार को कुवैत के लोगों के नाम जारी बयान में कहा कि ईरान अपने सैन्य अभियान को तब तक जारी रखेगा, जब तक क्षेत्र से अमेरिकी सेना पूरी तरह नहीं हट जाती. बयान में अमेरिका को कब्जा करने वाली और संसाधनों की लूट करने वाली ताकत बताया गया है.

कुवैत में बढ़ा तनाव उस समय और गहरा गया, जब एक दिन पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने जॉर्डन के अल-अजराक एयरबेस पर जवाबी मिसाइल हमला किया है. ईरान का कहना था कि इस हमले में अमेरिका के एफ-35 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए. हालांकि, अमेरिकी सेना ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. सेना का कहना है कि हमले में किसी भी अमेरिकी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसकी सभी सैन्य इकाइयां पूरे क्षेत्र में पूरी तरह तैयार हैं.

पाकिस्तान में बड़ा धमाका, बलूचिस्तान की कोयला खदान में 32 लोगों की मौत

बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट हुआ है. क्वेटा के पास सुरांज इलाके में स्थित खदान में धमाके के बाद उसका बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे दर्जनों मजदूर मलबे में दब गए.

अब तक इस हादसे में कम से कम 32 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. वहीं कई मजदूर अभी भी जमीन के नीचे फंसे बताए जा रहे हैं. राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं, लेकिन खदान के अंदर हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.

क्यों हुआ धमाका?

अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. आशंका जताई जा रही है कि खदान के भीतर गैस जमा होने की वजह से धमाका हुआ, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

क्या बोले खनन मंत्री?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान के खान और खनिज विकास मंत्री शोएब नोशेरवानी ने बताया कि विस्फोट के समय परिसर के ढह चुके हिस्से में 36 लोग मौजूद थे. प्रांत के खान निरीक्षक मुहम्मद आतिफ ने बताया कि 4,000 फीट (1,219 मीटर) की गहराई पर बचाव कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि हमें कुछ खनिकों के जीवित मिलने की उम्मीद है, लेकिन संभावना कम है. क्षेत्र के एक वरिष्ठ सरकारी खनन अधिकारी अब्दुल गनी बलूच ने कहा कि एक दूसरे के करीब स्थित दो खदानें एक शक्तिशाली मीथेन गैस विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गईं. यह विस्फोट प्रांतीय राजधानी क्वेटा के पास स्थित एक दूरस्थ क्षेत्र सोरेंज में हुआ.

मृतक के परिजनों को मिलेगा 5 लाख रुपये मुआवजा

खनिज विकास मंत्री नोशेरवानी ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान सरकार हर मृतक मजदूर के परिवार को 5 लाख पाकिस्तानी रुपये (करीब 1,800 अमेरिकी डॉलर) का मुआवजा देगी.

भिवंडी में चार मंजिला कोहिनूर अपार्टमेंट ढहा, 9 की मौत

भिवंडी। मुंबई से सटे भिवंडी शहर के भंडारी कंपाउंड स्थित गंगाराम वाड़ी इलाके में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब अतिजर्जर घोषित कोहिनूर अपार्टमेंट अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह गया। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुरुवार रात करीब साढ़े 11 बजे अचानक तेज धमाके के साथ इमारत का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद भिवंडी अग्निशमन दल, पुलिस, एनडीआरएफ तथा टीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया।

यूपी की ग्राम पंचायतों में खुलेंगी 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और डिजिटल संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. राज्य की ग्राम पंचायतों में जल्द ही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी. इस पहल का उद्देश्य गांवों के छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और अन्य पाठकों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराना है. डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होने के बाद ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई के लिए जरूरी ऑनलाइन सामग्री और डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी. इससे उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अच्छी लाइब्रेरी या आधुनिक अध्ययन केंद्रों के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता है.

गांवों में मिलेगा आधुनिक पढ़ाई का माहौल

डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को इंटरनेट और तकनीक आधारित अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. यहां ई-बुक, डिजिटल नोट्स, ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री और विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारी तक पहुंच आसान हो सकेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्र संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पीछे रह जाते हैं. ऐसे में पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनने से उन्हें अपने आसपास ही पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सकता है. यह पहल गांवों और शहरों के बीच डिजिटल शिक्षा के अंतर को कम करने में भी सहायक हो सकती है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को लाभ

डिजिटल लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा उन युवाओं को मिल सकता है, जो सरकारी नौकरी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. गांवों में कोचिंग संस्थान और बड़े पुस्तकालय सीमित होने के कारण कई विद्यार्थियों को दूरदराज के शहरों का रुख करना पड़ता है. नई डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए युवाओं को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, शैक्षणिक प्लेटफॉर्म और जरूरी जानकारी तक पहुंच मिल सकेगी. इससे तैयारी पर होने वाला खर्च कम करने और समय बचाने में भी मदद मिल सकती है. आज शिक्षा का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यमों से जुड़ चुका है. ऑनलाइन कक्षाएं, ई-पुस्तकें, वीडियो लेक्चर और डिजिटल टेस्ट जैसी सुविधाएं छात्रों की पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं. ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होने से ग्रामीण विद्यार्थियों को भी इन संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा.

'पापा के सिर पर पांच टांके थे, यूनिफार्म खून से लाल थी', घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की आपबीती

नई दिल्ली। दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन और 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों ने आपबीती सुनाई। पुलिस सिपाही की बेटी गुंजन ने बताया कि प्रोटेस्ट के दौरान मेरे पिता फ्रंटलाइन में थे। जब वो घर आते थे, तो यही कहते थे कि ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथी उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनके सिर पर 5 टांके थे। यूनिफार्म खून से लाल थी। सोशल मीडिया में मेरे ही पिता को क्रिमिनल बता रहे थे।

दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन और 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आज प्रेस वार्ता कर आपबीती सुनाई। घायल दिल्ली पुलिस एसीपी की पत्नी ने कहा, '20 जुलाई की देर रात जब वे घायल हालत में घर लौटे, तो वह पल मेरे और मेरी दो साल की बेटी, दोनों के लिए बेहद दर्दनाक और सदमे वाला था। मेरे साथ यहां दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के परिवार के अन्य सदस्य भी हैं और हम अपनी आपबीती आपके साथ साझा करना चाहते हैं।

प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली पुलिस में एएसआई की पत्नी सीमा ने बताया कि मैंने 20 जुलाई शाम 7 बजे पति को कॉल

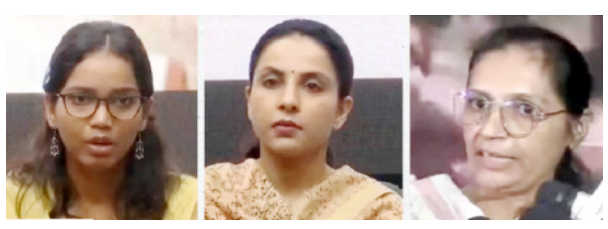

मिलाया तो वो अस्पताल में थे और इलाज करा रहे थे। उन्होंने बताया कि भीड़ में शरारती तत्व एक्टिव हो गए थे। उन्होंने पत्थर और हथियारों से पुलिस बल को घायल कर दिया था। फिर उनका फोन बंद हो गया। मुझे डर लग रहा था। 11 बजे वो घर आए, उन्होंने बताया कि संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसे तोड़ा और पुलिस फोर्स पर हमला किया। ड्यूटी के दौरान मिला हेलमेट पूरी तरह टूट गया था। इससे मेरी रूह काप गई थी। मैं संसद में बैठे गए प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारे पुलिसकर्मी और परिवार है, उसने अधिकारों और हमलों के बारे में संसद में सवाल किए जाए। 20 तारीख के बाद ये ही नेरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ ओर ही है।

एक पुलिस जवान की बेटी गुंजन के अनुसार, मेरे पिता फ्रंटलाइन में थे। जब वो घर आते थे, तो कहते थे कि ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथी उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनके सिर पर पांच टांके थे। यूनिफार्म खून से लाल थी। सोशल मीडिया में मेरे ही पिता को क्रिमिनल बता रहे थे। जिन्होंने मेरे पिता के साथ ये किया वो पुलिसवालों को क्रिमिनल साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। इसके बाद हम भी सुप्रीम कोर्ट गए। हमारी बात रखी गई।

घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का कहना है कि प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं, गुंडे थे। प्रदर्शनकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी की पत्नी अवनीत कौर ने कहा की अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि एक पुलिस अधिकारी सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं होता। बल्कि उसके पीछे उसका एक परिवार होता है, उसकी पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता, जो हर पल घर पर उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार करते हैं।

अमेरिका-ईरान युद्ध में अब तक कितने भारतीयों की मौत? संसद में सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में करीब 3 साल से तनाव व्याप्त है. पहले इजराइल और हमास के बीच चली जंग से पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में था और उसके बाद अमेरिका-इजराइल और ईरान में बीच हो रही जंग ने हर किसी को परेशान कर दिया है.

खास बात है कि इस जंग का दंश सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा. मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्धों का असर भारत पर भी साफ दिखाई दे रहा है. दरअसल, इस युद्ध के दौरान, कई भारतीय भी इस युद्ध में झुलसे हैं. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध में इस साल कई भारतीयों की मौत हुई है.

अमेरिका-ईरान युद्ध में अब तक 16 भारतीयों की गई जान

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, मध्य पूर्व में इस साल शुरू हुए संघर्ष के बाद से अब तक 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है. इसमें 10 लोग ऐसे थे, जो जहाजों पर काम करते थे. ये जानकारी संसद में खुद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक संसद सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए दी.

किस देश में कितने लोगों की मौत हुई?

दरअसल, सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने लिखित सवाल में सरकार से पूछा था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस साल शुरू हुए युद्ध में कितने भारतीयों की मौत हुई है. लिखित सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में 16 भारतीयों की मौत हुई है. 16 मौतों में एक मौत सऊदी अरब में, दो कुवैत में, आठ ओमान में, एक ईरान में चार भारतीयों की मौत यूएई में हुई है. 16 मृतकों के अलावा, 75 भारतीय भी घायल हुए हैं.

कतर में 12 भारतीयों की मौत

कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि सघंर्ष से अलग एक हादसे में कतर के रास लफ्फान गैस सुविधा में 12 भारतीयों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि सरकार ने मृतकों के परिजनों के शवों को भारत लाने में पूरी मदद की है.

10 लाख रुपये की आर्थिक मदद कर रही भारत सरकार

राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे बताया कि घायल लोगों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज करवाया गया. भारतीय दूतावास ने परिवार से संपर्क बनाए रखा और उनके भारत लौटने में मदद की. युद्ध क्षेत्र में काम करने वाले जहाजी कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का एक्स-ग्रेशिया मुआवजा दिया जा रहा है.

महत्वपूर्ण ख़बर

संग्रहालय निर्माण में पुरानी निर्माण पद्धति और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में गुरूवार को कोठी महल स्थित निमार्णाधीन एवं प्रगतिरत 'वीर भारत संग्रहालय' का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने जीर्णोद्धार कार्य में इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री (कंस्ट्रक्शन मटीरियल) का निरीक्षण किया और स्थल पर काम कर रहे श्रमिकों व कारीगरों से बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना।

उन्होंने निर्देश दिए कि रिनोवेशन में पुरानी एवं पारंपरिक निर्माण पद्धतियों का ही अनुसरण किया जाए, जिससे इमारत की मौलिकता बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की बात कही।

वीर भारत संग्रहालय का जीर्णोद्धार कार्य उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराया जा रहा है।

विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता

- भोपाल। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि "जनता की निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र-संस्कृति की रक्षा तथा सर्वांगीण विकास की गति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना ही हमारी सरकार का मूल संकल्प है"। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिवस पर भोपाल के वार्ड क्रमांक 54 में आयोजित विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि- पूजन समारोह में व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से क्षेत्र में निरंतर विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है, जहाँ मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहरों के संरक्षण को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है।

केन्द्रीय दूरसंचार और म.प्र. सरकार के मध्य हुआ ऐतिहासिक एमओयू

भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में होगा स्थापित: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग हब एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन निर्माण के लिए नई दिल्ली में हुआ एमओयू ऐतिहासिक कदम है। अब मध्यप्रदेश की धरती पर निर्मित संचार उपकरण देश-दुनिया को उपलब्ध होंगे। ये उपकरण मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी के फेथ इन मध्यप्रदेश का जरिया बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ हुई राउंड टेबल मीटिंग में 3500 करोड़ रुपए के निवेश तथा 14 हजार से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के एमओयू हस्ताक्षर समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री पी.एस. चंद्रशेखरन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिस पर देश और दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की धरती पर ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के रूप में एक नए दौर की शुरूआत हो रही है। आज भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की शुरूआत से निर्यात बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से स्मार्ट एआई मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस, हेल्थ और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में आधारशिला तैयार हो चुकी है। आज देश में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेटवर्क से टेलीकॉम सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिली हैं। ग्वालियर अंचल को ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की सौगात मिलना सोने पर सुहागा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित टेलीकॉम

सेक्टर के निवेशकों को ग्वालियर में निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलवाया कि जो देश में कहीं नहीं मिलेगा, वो मध्यप्रदेश में निश्चित रूप से मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास में तेज गति से विकास के लिए मध्यप्रदेश की अलग ही धाक बनी है। प्रदेश की संस्कृति गौरवशाली है। इसमें कोहिनूर के हीरे की तरह ग्वालियर का विशेष महत्व है। यहां 170 एकड़ क्षेत्र में प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले देश के पहले टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन का इंटीग्रेडेट इकोसिस्टम स्थापित होगा। इस जोन में डिजाइन से टेस्टिंग तक मैन्यूफैक्चरिंग से डेवलपमेंट तक सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक भविष्य की वैल्यू चेन का निर्माण होगा। देश में 5जी, 6जी उपकरण, ऑप्टिकल फायबर उपकरण, सेमीकंडक्टर उपकरण, डिवाइस नेटवर्किंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मिलेगा। साथ ही इंजीनियरिंग सर्विसेस, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, तकनीकी संस्थानों के साथ उत्तर भारत का नया केंद्र बनेगा।

मध्यप्रदेश को मिली हैं 5 बड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को 5 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क धार जिले में बनाया जा रहा है। यह कपास उत्पादक किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी उपलब्धि है। रायसेन जिले में बीईएमएल के माध्यम से आधुनिक मेट्रो और रेलवे कोच निर्माण के लिए प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। बीना में पेट्रोलियम रिफायनरी के साथ ही भारत रत्न से सम्मानित स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, वह भी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल के माध्यम से पूर्ण होगा। केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश को 2 रिवर लिंक प्रोजेक्ट की सौगात मिली हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता बनना नहीं, बल्कि उनका डिजाइन, विकास और निर्माण भारत में कर उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों तक निर्यात करना है। उन्होंने कहा कि यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन 'डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया' के विजन को साकार करेगा। इससे भारत वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी। केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री श्री पी.एस. चंद्रशेखरन ने भी संबोधित किया।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर को देश के अत्याधुनिक टेलीकॉम उपकरण विनिर्माण, परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 170.5 एकड़ में विकसित होने वाला यह प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक इकोसिस्टम उद्योगों को उत्पादन प्रारंभ करने के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध कराएगा। परियोजना का विकास विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत तथा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। एमपीआईडीसी इस परियोजना का मास्टर डेवलपर होगा। परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 493 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें 270.24 करोड़ रुपए अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब एवं लैब इकोसिस्टम, 180 करोड़ रुपए आंतरिक अधोसंरचना, 34.20 करोड़ रुपए भवन एवं प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, 5 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी सेंटर तथा 4 करोड़ रुपए निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों को प्राथमिकता से करवाएं रोजगार उपलब्ध

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में गुरूवार को विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक विकास एवं निवेश परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों को प्राथमिकता पर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। किसानों को औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो एवं उद्योगों को भी

आवश्यकतानुसार कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों, आधुनिक अधोसंरचना और निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रदेश में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एमपीआईडीसी के कार्यपालक निदेशक श्री राजेश राठौड़ ने जिले में संचालित एवं प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं, औद्योगिक अधोसंरचना विकास, भूमि आवंटन तथा निवेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेसर्स पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 1,266 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इस इकाई का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। इस परियोजना से लगभग 800 प्रत्यक्ष तथा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक क्षेत्र में 50.05 करोड़ रुपये की लागत से निमार्णाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्माणाधीन रेप्टाइल पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का किया निरीक्षण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को रेप्टाइल पार्क (सर्प उद्यान) एवं अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि होमगार्ड के जवानों को भी सांप पकड़ने और सुरक्षित रेस्क्यू करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई बार रिहायशी क्षेत्रों में सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे समय प्रशिक्षित होमगार्ड जवान नागरिको की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सर्पों का सुरक्षित रेस्क्यू कर सकेंगे। इससे वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और आमजन में भय की स्थिति भी कम होगी। उज्जैन को वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बसंत विहार क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत निमार्णाधीन रेप्टाइल पार्क (सर्प उद्यान) एवं अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से परियोजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन समन्वय से करें: राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल ने की सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के क्रियान्वयन की समीक्षा

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजाति कल्याण का प्रतिबद्ध प्रयास है। संबंधित विभाग इस अधिनियम के क्रियान्वयन को विशेष प्रयासों से और अधिक प्रभावी बनाए। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन कार्य में आवश्यकता अनुसार स्थानीय जन प्रतिनिधियों और ज़िम्मेदार नागरिकों का सहयोग लें।

राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को लोकभवन में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। सांदीपनि सभागार में आयोजित बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने बैठक में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। सामुदायिक वन संसाधन, संरक्षण और प्रबंधन के अधिकारों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा की समुचित प्रक्रिया

अपनाई जाये। समस्त प्रक्रिया को ग्राम सभा में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने पेसा ग्रामों में अधिनियम की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के कार्यों और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखें। समय-समय पर वित्तीय प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों का निरीक्षण भी कराएं।

राज्यपाल श्री पटेल को अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि 15 अगस्त की विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से वन संसाधन अधिकार अभियान को और आगे बढ़ाया जायेगा। स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता के विशेष प्रयास किए जायेगें। अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विभागों का सहयोग भी लिया जायेगा। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री गुलशन बामरा ने प्रदेश भर में वनाधिकार कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी दी। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्यों पर चर्चा की। प्रमुख सचिव वन श्री राघवेंद्र सिंह ने आगामी दिनों में वन संसाधन अधिकार से संबंधित लंबित कार्यों को तेजी से पूर्ण करने की बात कही।

बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री ई. रमेश कुमार, जनजाति प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती मीनाक्षी सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) श्री शुभरंजन सेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री मनोज कुमार अग्रवाल और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

भर्ती विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन

कोर्ट में पेश करने होंगे फाइनल रिजल्ट, 5 कैटेगरी में होगी मामलों की सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रोसेस से जुड़े कई साल पुराने विवादों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिटस विवेक रूसिया और जस्टिटस प्रदीप मित्तल की बेंच ने विभिन्न वर्षों में हुई चयन प्रक्रियाओं के सभी फाइनल रिजल्ट को अदालत में तलब किया है।

अदालत ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि इन सभी चयन परिणामों को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विकास

शर्मा के सामने तुरंत लाया जाए। सालों से लंबित मामलों के लिए हाईकोर्ट का नया प्लान

भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं के अंबार और लंबे समय से पेंडिंग पड़े मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए हाईकोर्ट ने एक विशेष रणनीति बनाई है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को 5 कैटैगरी में बांटकर सुनवाई करने की योजना बनाई है- इसके अलावा चयन प्रक्रिया से बाहर हुए या वंचित रहे अभ्यर्थियों की याचिकाओं को एक अलग श्रेणी में रखकर अलग से सुनवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान जनभागीदारी के तहत गेस्ट फेकल्टी ने 25 % आरक्षण और 10 साल की आयु सीमा में छूट देने की मांग उठाई। याचिकाकताओं का तर्क है कि जब वे समान योग्यता और समान कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें इन लाभों से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मशहूर 'मनीष गुप्ता मामले' के फैसले का हवाला दिया है।

खंडवा में साढ़े 10 घंटे तक चला मौत से मुकाबला

खंडवा। मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल एसडीईआरएफ ने एक बार फिर साहस का परिचय देकर चार जिंदगियों को बचा लिया।

मामला खंडवा जिले के थाना जावर क्षेत्र के हांडीकुंड में सुक्ता और आबना नदी के बीच हन्दीकुंडी स्थित टापू का है, जहां चार युवक फंस गए थे। लगभग साढ़े 10 घंटे तक चले बेहद खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार तड़के 4:45 बजे सभी को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज!

एमपी में खुले बोरवेल और सेप्टिक टैंक से हादसों पर अब होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई

भोपाल। प्रदेश में अब खुले सेप्टिक टैंक या बोरवेल से हादसे हुए तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन से लेकर बर्खास्त तक करने की कार्रवाई की जाएगी। ओंकारेश्वर की घटना के बाद मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ऐसी दुर्घटनाओं पर जवाबदेही तय कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रकरण की विभागीय जांच की जाएगी। दुर्घटना में लापरवाही करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा। अगर विभागीय जांच में दोषी पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। ओंकारेश्वर के पहले भी प्रदेश में खुले और असुरक्षित सेप्टिक टैंकों के कारण कई हादसे हुए हैं। पिछले माह जून में ही बैतूल जिले के मुलताई में और जबलपुर में अक्टूबर 2025 में दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी ऐसी ही कई घटनाएं हुई हैं। राज्य शासन द्वारा सेप्टिक टैंक और बोरवेल खुले न छोड़े जाने की सख्त हिदायत है। कार्रवाई के लिए शासन ने गाइडलाइन भी बनाई है, लेकिन सख्ती न होने से बार-बार हो रही ऐसी लापरवाही आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रही है।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे युवक को किया बरी, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट पर लगी मुहर

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में निचली अदालत (सेशन कोर्ट) के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने नाबालिक सेदुष्कर्म के आरोपी शख्स को बरी कर दिया है। अदालत ने रेडियोलॉजिस्ट की उस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, जिसके मुताबिक पीड़िता घटना के समय बालिग (18 वर्ष से अधिक) थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा- पीड़िता की उम्र के निर्धारण के मामले में रेडियोलॉजिस्ट की मेडिकल राय, स्कूल के दाखिला रजिस्टर (जिसमें जन्मतिथि 19 दिसंबर 2003 दर्ज थी) की तुलना में अधिक भरोसेमंद लगती है। घटना 30 जुलाई 2021 की बताई गई थी, जिसके बाद 2 अगस्त 2021 को एक महिला डॉक्टर ने पीड़िता की जांच की।

उम्र के सही आकलन के लिए रेडियोलॉजिस्ट की भी राय ली गई थी। रेडियोलॉजिस्ट की जांच में सामने आया कि पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक थी। सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष ने इस एक्स-रे रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया था। हालांकि यह केस फाइल का हिस्सा थी। कोर्ट ने आगे कहा- वारासिवनी ट्रायल कोर्ट ने बिना कोई कारण बताए इस रिपोर्ट और डॉक्टर की राय को नजरअंदाज करने की भूल की। इसके अलावा, पीड़िता के स्कूल के प्रिंसिपल भी कोर्ट में यह बताने में असमर्थ रहे कि स्कूल रजिस्टर में किस आधार पर लड़की की जन्मतिथि दर्ज की

गई थी।

आरोपी के वकील का पक्ष सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। उन्होंने कोर्ट के सामने मैरिज सर्टिफिकेट (शादी का प्रमाण पत्र) पेश करते हुए स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को चुनौती दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा- अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि घटना वाले दिन (30 जुलाई 2021) पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया कि पीड़िता को डरा-धमकाकर या जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया गया था, जिससे यह मामला दुष्कर्म (फंस्त्री) की श्रेणी में आए।

क्या था पूरा मामला?

पीड़िता के परिवार के मुताबिक, कक्षा 12वीं की छात्रा 21 जुलाई 2021 को अचानक गायब हो गई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। 31 जुलाई 2021 को लड़की को बेंगलुरु से बरामद किया। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया था- मां की डांट से नाराज होकर वह 19 जुलाई 2021 को घर छोड़कर अकेली निकल गई थी। रास्ते में उसे आरोपी मिला, जिसने शुरूआत में उसे घर वापस जाने की सलाह दी। जब उसने इनकार कर दिया, तो वह उसे अपने दोस्त के घर ले गया। इसके बाद दोनों नागपुर और हैदराबाद होते हुए 24 जुलाई को बेंगलुरु पहुंचे, जहां 30 जुलाई को आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल, सीमा ने ब्रॉन्ज पर साथा निशाना

ग्लासगो। खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगाता जारी है. भारत को दो और मेडल मिल चुके हैं. वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने गुरुवार देर रात भारत को सिल्वर मेडल दिलाया. वहीं देश को सीमा कालीरमन ने विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया. अब तक भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 17 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 3 गोलड और, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मैडल शामिल हैं.

लवप्रीत सिंह ने दिलाया भारत को सिल्वर

वेटलिफ्टर में लवप्रीत सिंह ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल दिया है. वो देश को गोल्ड मेडल दिलाने से सिर्फ एक कदम से चूक गए. लवप्रीत ने यह मेडल पुरुषों की 110+ किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में जीता है. लवप्रीत ने कुल 388 किग्रा वजन उठाया, जो न्यूजीलैंड के डेविड लिटी से सिर्फ 1 किग्रा कम था. लिटी ने 389 किग्रा के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वहीं इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ्स ने कुल 356 किग्रा (165 + 191) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला. लवप्रीत सिंह ने स्नैच में सबसे ज्यादा भार उठाया. इसके साथ ही वो स्नैच में सबसे ज्यादा भार उठाने वाले वेटलिफ्टर रहे, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में 168 किग्रा वजन उठाया. इसके बाद 173 किग्रा वजन भी उठाया. उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 176 किग्रा वजन उठाकर दूसरे स्थान पर चल रहे न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी के खिलाफ 10 किग्रा वजन की बढ़त हासिल कर ली थी. इसके बाद 'क्लीन एंड जर्क' में उन्होंने 205 किग्रा और 212 किग्रा वजन उठाया और फिर अपनी आखिरी लिफ्ट में 217 किग्रा उठाने की हिम्मत दिखाई. स्नैच में 166 किग्रा वजन उठाने वाले डेविड लिटी ने क्लीन एंड जर्क में 223 किग्रा का निर्णायक वजन उठाकर लवप्रीत से बहुत कम अंतर से बढ़त बनाते हुए खिताब अपने नाम किया.

सीमा कालीरमन ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्कॉटस्टाउन स्टेडियम में आयोजित विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल में सीमा कालीरमन ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया. जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड जीता है. भारत की निधि रानी 57.10 मीटर के चौथे स्थान पर रहीं. उन्होंने तीसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन पदक से चूक गईं. निधी के सभी 6 प्रयास वैलिड थे, जिसमें उन्होंने क्रमशः 53.19 मीटर, 55.67 मीटर, 57.10 मीटर, 55.07 मीटर, 53.82 मीटर, 53.82 मीटर और 55.39 मीटर की दूरी तय की थी. सीमा कालीरमन ने 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. सीमा ने अपने दूसरे प्रयास में 57.32 मीटर की दूरी तय की थी. वहीं जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड जीता है. भारत की निधि रानी 57.10 मीटर के चौथे स्थान पर रहीं. उन्होंने तीसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन पदक से चूक गईं. निधी के सभी 6 प्रयास वैलिड थे, जिसमें उन्होंने क्रमशः 53.19 मीटर, 55.67 मीटर, 57.10 मीटर, 55.07 मीटर, 53.82 मीटर, 53.82 मीटर और 55.39 मीटर की दूरी तय की थी. वहीं, कनाडा की जूलिया टंक्स ने सिल्वर मेडल मिला. सीमा कालीरमन ने 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. सीमा ने अपने दूसरे प्रयास में 57.32 मीटर की दूरी तय की थी. वहीं जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड जीता है. भारत की निधि रानी 57.10 मीटर के चौथे स्थान पर रहीं. उन्होंने तीसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन पदक से चूक गईं. निधी के सभी 6 प्रयास वैलिड थे, जिसमें उन्होंने क्रमशः 53.19 मीटर, 55.67 मीटर, 57.10 मीटर, 55.07 मीटर, 53.82 मीटर, 53.82 मीटर और 55.39 मीटर की दूरी तय की थी.

महत्वपूर्ण ख़बर

अफगानिस्तान क्रिकेट के नये फील्डिंग कोच बने मैकडरमॉट

- सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज शेन मैकडरमॉट को अफगानिस्तान का नया असिस्टेंट और फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। आयरलैंड के खिलाफ अगले माह होने वाली एकदिवसीय सीरीज के पहले इस बदलाव से टीम को लाभ होने की की संभावना है। मैकडरमॉट 1 अगस्त को अफगानिस्तान टीम से जुड़ेंगे। अफगान टीम को आयरलैंड के खिलाफ पांच मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलनी है। मैकडरमॉट मुख्य कोच रिचर्ड पाइबस के साथ मिलकर काम करेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरूआत में जोनाथन ट्रॉट की कोच की भूमिका संभाली थी।

दिलीप की स्वर्णिम दौड़, बासिल ने कब्जाई चांदी

ग्लासगो। भारतीय एथलीट दिलीप गावित ने पुरुषों की टी-47 100 मीटर पैरा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।

दिलीप गावित ने पुरुषों की टी-47 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का समय लेकर गेम्स रिकॉर्ड और सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ समय बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं, उनके साथी मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ ने 10.83 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ, दिलीप महादु गावित पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए।

साथ ही, महिला शॉट पुट एफ 57 इवेंट में शर्मिला के गोल्ड मेडल के बाद, राष्ट्रमंडल खेल पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले वे कुल मिलाकर दूसरे भारतीय पैरा एथलीट हैं। एथलेटिक्स में, मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.09 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया और बर्मिंघम 2022 की अपनी उपलब्धि को दोहराया। साथी भारतीय लोकेश सत्यनाथन 7.97 मीटर के साथ पांचवें स्थान पर रहे। पैरा एथलेटिक्स में, सागर थायत और देवेंद्र कुमार पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ42-44/एफ61-64 फाइनल में क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर रहे।

भारतीय हॉकी टीम की नारंगी जर्सी पर विवाद

पूर्व कप्तान रास्किन्हा बोले, नीला रंग हमारी पहचान

नई दिल्ली। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हो गया है। दशकों से नीली जर्सी में खेलने वाली भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप में नारंगी रंग की किट में नजर आएगी। भारतीय हॉकी के दिग्गज और पूर्व कप्तान विरेन रास्किन्हा ने जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

वहीं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने इस फैसले का बचाव किया है। रास्किन्हा ने कहा कि नीले रंग की जर्सी हमारी पहचान थी। उधर, टिर्की ने कहा कि मौजूदा जर्सी का रंग खिलाड़ियों की पसंद थी। हॉकी इंडिया ने 27 जुलाई को पुरुष और महिला टीमों की नई जर्सी लॉन्च की थी। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विरेन रासकिन्हा ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय टीम की पहचान हमेशा नीली जर्सी रही है और इसे बदलने का कोई तर्क समझ नहीं आता। विरेन रासकिन्हा जूनियर वर्ल्ड कप 2001 जीतने वाली टीम के सदस्य थे और सीनियर टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। उन्होंने एथेंस ओलंपिक 2004, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2006 और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें अपने दौर के बेस्ट मिडफील्डर्स में गिना जाता है।

वर्ल्ड कप के बाद बदल सकते हैं जर्सी

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार टिर्की ने कहा कि यह फैसला खिलाड़ियों, कप्तानों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के सुझाव पर लिया गया। अगर वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों को यह जर्सी पसंद नहीं आती है, तो भविष्य में इसे बदला भी जा सकता है।

जो रूट इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान, स्टीफन फ्लेमिंग नए कोच

लंदन। जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बनाए गए हैं। रूट हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले बेन स्टोक्स की जगह लेंगे। इसके साथ ही स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड का नया टेस्ट कोच बनाया गया है। कप्तान के रूप में रूट का पहला असाइनमेंट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होने वाली पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज होगी।

रूट ने 13 फरवरी, 2017 से 15 अप्रैल, 2022 तक 64 मैचों में इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी की। करीब पांच साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए पिछले कुछ महीने काफी उथल-पुथल भरे रहे हैं।

मैकुलम वनडे और टवेंटी-20 टीम के हैड कोच बने रहेंगे

मैकुलम टेस्ट टीम के कोच पद से हट चुके हैं, लेकिन अगले साल के अंत तक इंग्लैंड की वनडे और टी-20 टीम के हेड कोच बने रहेंगे। फ्लेमिंग और मैकुलम लंबे समय से करीबी दोस्त और पेशेवर सहयोगी रहे हैं। ऐसे में अगर फ्लेमिंग टेस्ट टीम की कमान संभालते हैं तो दोनों के बीच तालमेल इंग्लैंड के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

कारोबार

पीवीसी आयात पर सरकारी पहरा, क्या फिर बिगड़ने वाला है आपके घर का बजट?

नई दिल्ली। जल्द ही घर बनाना और भी महंगा होने वाला है। खेती के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाना या घर की वायरिंग कराना आम आदमी के बजट को बढ़ाने वाला है। सरकार ने सस्ते विदेशी प्लास्टिक कच्चे माल पर नकेल कसने का फैसला किया है। लेकिन इस नीतिगत फैसले का सीधा झटका आम जनता की जेब पर लगने वाला है।

क्या है पूरा मामला?

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने हाल ही में सस्पेंशन - ग्रेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (एस-पीवीसी) रेजिन के आयात नियमों को सख्त कर दिया है। यह एक तरह का प्लास्टिक कच्चा माल है, जिसका इस्तेमाल घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी के पाइप, बिजली के तारों की कोटिंग, खिड़कियों की फ्रेम, प्लास्टिक पैकिंग, कई चिकित्सा उत्पादों और यहां तक कि जूतों के सोल बनाने में होता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एस- पीवीसी रेजिन पर न्यूनतम आयात मूल्य 0.76 डॉलर (लगभग 64 रुपये) प्रति किलोग्राम या उससे कम कीमत वाले आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है।

घरेलू कीमतें बढ़ने की आशंका

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस कदम से घरेलू पीवीसी रेजिन की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.63 अरब डॉलर

का रेजिन आयात किया था। चीन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, इसके बाद जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, थाइलैंड, अमेरिका, सिंगापुर एवं वियतनाम का स्थान रहा। जीटीआरआई के मुताबिक, इन देशों से आयात की औसत कीमत 0.65 डॉलर से 0.75 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच रही, जो डीजीएफटी की तय राशि 0.76 डॉलर से कम है। ऐसे में मौजूदा आयात का बड़ा हिस्सा अब अंकुश के दायरे में आ जाएगा।

घर से लेकर खेत तक दिखेगा असर

घर बनाने में पीवीसी पाइप, फिटिंग और बिजली के तारों की बड़ी खपत होती है। जब कच्चा माल महंगा होगा, तो कंपनियां इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर डालेंगी। खेती- किसानी और पानी की पाइपलाइनों में 70 से 80 फीसदी पीवीसी का इस्तेमाल होता है। पाइप महंगे होने से किसानों का बजट बिगड़ेगा। इस कच्चे माल का इस्तेमाल पैकेजिंग फिल्मों और आम जूतों-चप्पलों में भी होता है, जिससे दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।

छोटे उद्योगों के लिए बड़ा खतरा

भारत में पीवीसी पाइप और केवल बनाने वाली हजारों छोटी और मझोली इकाइयां हैं। सस्ता माल न मिलने से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इसका असर दोतरफा होगा, या तो उत्पाद महंगे होंगे, या फिर कई छोटी इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। देश कुल जरूरत का 64 फीसदी एस-पीवीसी रेजिन आयात करता है।

हल्की बढ़त के साथ शेयर बाजार की शुरूआत

सेंसेक्स 49 अंक चढ़ा; निफ्टी 24350 के करीब

मुंबई। शेयर बाजार में हल्की बढ़त के साथ रुपये ने भी दिखाई मजबूती। सेंसेक्स-निफ्टी की शुरूआत, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया तनाव के असर के बारे में जानिए इस रिपोर्ट में। घरेलू शेयर बाजार ने शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में मामूली बढ़त के साथ शुरूआत की। शुरूआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 49.91 अंक चढ़कर 77,970.95 अंक पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी भी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,343.65 अंक पर कारोबार कर रहा था।

डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत

विदेशी निवेश बढ़ने और दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में रुपया मजबूत हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे चढ़कर 95.30 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, डॉलर के मजबूत होने से रुपये की बढ़त सीमित रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने यह जानकारी दी।

विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.40 के स्तर पर खुला। बाद में इसमें मजबूती आई और यह 95.30 के स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले कारोबारी बंद भाव के मुकाबले 20 पैसे की बढ़त है। रुपया लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ है। गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे चढ़कर 95.50 पर बंद हुआ था।

रुपये पर क्या है एक्सपर्ट की राय?

चॉइस ब्रोकिंग के कमोडिटी और करंसी एनालिस्ट (टेक्निकल रिसर्च) आमिर मकदा ने कहा कि शुक्रवार को रुपये में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट से रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूती मिल सकती है। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की लगातार दखल देने की उम्मीद भी रुपये को सहारा दे रही है।

इस बीच, गुरुवार को अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर कई मिसाइल हमले किए। दोनों देशों के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। इससे जल्द समाधान की उम्मीद कम होती दिख रही है। कुछ समय की शांति के बाद एक बार फिर बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इस लड़ाई के और देशों तक फैलने की आशंका जताई जा रही है। जॉर्डन ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन ईरान की मिसाइलों को रोकने का दावा किया। वहीं, कुवैत ने कहा कि देश के उत्तरी हिस्से में हुए एक हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट

सोने की खरीद 8.3 टन घटी, पहले से ज्यादा ढीली हुई जेब

नई दिल्ली। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारत में सोने की मांग 6% घटकर 131.4 टन रह गई, लेकिन रिकॉर्ड कीमतों के कारण लोगों का खर्च 50% बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। उपभोक्ता अब हल्के और कम कैरट के गहने खरीद रहे हैं। वहीं, आयात शुल्क 15% होने के बाद सोने की तस्करी के मामलों में भी तेजी दर्ज की गई।

अप्रैल-जून 2026 तिमाही के दौरान भारतीय परिवारों ने कम सोना खरीदा, लेकिन फिर भी उनकी जेब कहीं ज्यादा ढीली हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय परिवारों ने एक साल पहले के मुकाबले इस साल अप्रैल-जून तिमाही में 8.3 टन कम सोना खरीदा, इसके बावजूद रिकॉर्ड कीमतों के कारण आम लोगों को 65,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़े।

इस दौरान भारत में सोने की औसत कीमत 1,50,744 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 94,875 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। कुल मांग घटकर 131.4 टन रह गई, जो

पिछले साल की समान अवधि में 139.7 टन थी। इसमें लगभग 6 फीसदी की तेज गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, कुल खरीदारी का मूल्य 50 फीसदी उछलकर 1.33 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

ग्राहकों ने बदली रणनीति: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत में क्षेत्रीय सीईओ सचिन जैन का कहना है कि भारतीय उपभोक्ता अब ऊंची कीमतों के हिसाब से ढल रहे हैं। खरीदारी का बजट वही रखने के लिए आम लोग अब कम कैरट और हल्के वजन के गहनों को तवज्जो दे रहे हैं। सोने की मांग को नियंत्रित करने, व्यापार घाटा कम करने और रुपये पर दबाव घटाने के लिए 13 मई को सोने पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया था। इसके बाद अवैध तरीकों से सोने की आवक में वृद्धि देखी गई। सरकार ने संसद में बताया कि प्रवर्तन एजेंसियों ने 13 मई से 30 जून के बीच 160.91 किलोग्राम सोना जब्त किया, जो एक अप्रैल से 12 मई के बीच जब्त किए गए 86.16 किलोग्राम के मुकाबले लगभग दोगुना है।

बढ़ रहा है टेलीकॉम मैनेजमेंट में स्कोप!

भारत का दूरसंचार उद्योग (टेलीकॉम इंडस्ट्री) विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम उद्योग है। कारण है विशाल जनसंख्या। जितनी जनसंख्या, उतने उपभोक्ता और जितने उपभोक्ता, उतना बड़ा उद्योग। टेलीकॉम सेक्टर में टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट आदि शामिल हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक दूरसंचार साधनों का उपयोग हो रहा है। साथ ही, सरकार ने ई-गवर्नेंस भी शुरू किया है। कुल मिलाकर, टेलीकॉम के क्षेत्र में करियर निर्माण की बहुत उजली संभावनाएं हैं। आप टेलीकॉम मैनेजमेंट में एमबीए करके बेहतर करियर बना सकते हैं।

क्या है एमबीए टेलीकॉम मैनेजमेंट

टेलीकॉम मैनेजमेंट में एमबीए दरअसल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का मेल है। यह कोर्स करके आप दूरसंचार के विस्तृत नेटवर्क को मैनेज करने की स्किल्स सीख सकते हैं। इस डिग्री से आप टेलीकॉम ऑपरेशंस के इन पहलुओं पर पकड़ बना सकते हैं- फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, रेग्युलेटरी, लीगल फ्रेमवर्क। यह कोर्स 2 साल का होता है।

कौन कर सकता है यह कोर्स

आप भी यह कोर्स कर सकते हैं, यदि आपके पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर्स डिग्री है और आपने कैट/ जीमैट/ जैट/ स्नैप/ सीमैट आदि जैसी कोई प्रवेश परीक्षा क्लियर कर ली है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से हैं, तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ होगा।

जरूरी स्किल्स

सूचना और संचार प्रणालियों की मूलभूत अवधारणाओं को समझने के अलावा कुछ और स्किल्स होना जरूरी है। इसके लिए स्वयं से ये सवाल पूछें -

- क्या आपका दिमाग सदा सक्रिय रहता है
- क्या आप निर्णयक्षमता के धनी हैं
- क्या आपको लगता है कि आप लोगों द्वारा भरोसा किए जाने लायक हैं
- क्या आप दूसरों से सीखने को तत्पर रहते हैं
- क्या आपमें मौजूदा ट्रैंड्स को चुनौती देने का साहस है
- क्या आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं
- क्या आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तत्पर रहते हैं

यदि इन सवालों के जवाब आप हां में देते हैं, तो आपमें यह कोर्स करने और टेलीकॉम मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए जरूरी स्किल्स हैं।

करियर ऑप्शंस

टेलीकॉम सेक्टर के आकार और विस्तार के बढ़ने के साथ ही, टेलीकॉम मैनेजमेंट में एमबीए करने के बाद अवसरों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। फ्रेशर हो या अनुभवी व्यक्ति, यदि कोई दृढ़ संकल्पित है, तो इस क्षेत्र में सफल हो सकता है। टेलीकॉम मैनेजमेंट में एमबीए करके आप इन क्षेत्रों में टेलीकॉम मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं- सेल्स एंड डिस्ट्रिब्यूशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, नेटवर्क प्लानिंग, सिक्योरिटी, टेलीकॉम कंसल्टिंग, इंटरनेशनल वॉइस ट्रेडिंग, टेलीकॉम रेग्युलेशन आदि। अनेक क्षेत्रों से जुड़ी सरकारी व प्राइवेट फर्म्स नई प्रतिभाओं को हायर करने को तैयार रहती हैं, जैसे- मोबाइल उत्पादक, ऑप्टिकल फाइबर उत्पादक, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर उत्पादक, वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडर्स (इंफोसिस/ माइक्रोसॉफ्ट/ विप्रो/ गूगल आदि), टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी फर्म्स आदि।

सैलरी पैकेज

युवा ग्रेजुएट्स की सैलरी 3 से 5 लाख प्रति वर्ष होती है। अनुभव के साथ बढ़ते-बढ़ते यह 30 लाख रुपए तक भी जा सकती है।

खेलों के मैदान में नाम भी, पैसा भी

विराट कोहली जब महज तीन साल के थे, तभी से उन्होंने हाथों में क्रिकेट बैट पकड़ना सीख लिया था और जिद करके खुद के लिए अपने पिता से गेंदबाजी कराया करते थे। 9 वर्षों तक ये यूं ही गली-मोहल्ले में शौकिया क्रिकेट खेलते रहे। फिर एक दिन उनके पिता को एक दोस्त ने बेटे को क्रिकेट ट्रेनिंग दिलाने की सलाह दी। उन्होंने सुझाव पर सोच-विचार किया और विराट का दाखिला एक एकेडमी में हो गया। आज वे सफलता के किस मुकाम पर हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि खेल के प्रति ऐसी ही कुछ खूबियां आपमें भी छिपी हों, जिन्हें समय रहते पहचानकर और उचित प्रशिक्षण के बाद आप भी सचिन तेंडुलकर, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, विश्वनाथन आनंद, मैरीकॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल आदि जैसे कामयाब खिलाड़ी बन सकते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस के अलावा बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, शूटिंग, बास्केटबॉल आदि खेल आज सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि बेहतरीन करियर भी बनते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्पोर्ट्स में सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही स्कोप है। आप चाहें, तो कोच, फिजिकल ट्रेनर, अंपायर, कमेंटेटर, स्कोरर, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स एडिटर, क्यूरेटर, फिजियोथैरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रैक्टिशनर, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर आदि के रूप में भी आकर्षक करियर बना सकते हैं।

करियर के अवसर

भारत में युवा प्रतिभाओं के लिए स्पोर्ट्स में करियर ऑप्शंस की कमी नहीं है। स्पोर्ट्स एकेडमीज से ट्रेनिंग के बाद आप खिलाड़ी के तौर पर राज्य स्तरीय इवेंट्स में खेलते हुए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। खिलाड़ी के तौर पर करियर खत्म होने के बाद स्पोर्ट्स कोच, कंसल्टेंट, अंपायर, रेफरी, टीम मैनेजर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सप्लायर आदि के रूप में करियर के अन्य ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। बीपीएड/ एमपीएड कोर्स करके स्कूल-कॉलेज में फिजिकल टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा क्यूरेटर भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। क्रिकेट मैचों के लिए अच्छी पिच क्यूरेटर ही तैयार करते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी एक स्पेशलाइज्ड करियर है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन दिनों इनकी खासी डिमांड है। एमबीबीएस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मेडिसिन का 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करके स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रैक्टिशनर बन सकते हैं।

पर्सनल स्किल

अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपमें प्रतिभा, रुचि और समर्पण हो बहुत जरूरी है। आधे-अधूरे मन से खेलकर इस फील्ड में कामयाबी पाना संभव नहीं है। खेलों के लिए कुछ बेसिक शारीरिक क्षमता होना बेहद जरूरी है। इसे फिटनेस ट्रेनिंग और कोचिंग से हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए आपको खेल भावना भी रखनी होगी। ग्राउंड पर खिलाड़ियों के सामने विपरीत परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करने का दबाव रहता है। इसलिए आपको मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होगा।

जंगलों को काटने से पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण वाइल्डलाइफ सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे में वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशन की जरूरत अब महसूस की जाने लगी है। एक वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशनिस्ट लुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण तो करता ही है, उसके कारणों की भी खोज करता है।

इसलिए बढ़ रहा है वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशन में स्कोप

अगर आप भी रोमांचक करियर की तलाश में हैं, तो वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशन का क्षेत्र आपके लिए श्रेष्ठ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में दुर्लभ जानवरों की हजारों प्रजातियां इस समय विलुप्त होने के कगार पर हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है, जंगलों का लगातार काटा जाना। हालांकि कई संगठनों के सामने आने के बाद अब हालात में कुछ परिवर्तन आया है लेकिन पूरी तरह से तस्वीर बदलने के लिए जरूरत है, वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशनिस्ट्स की। ये विशेषज्ञ जानवरों के आवास पर शोध कर उनका संरक्षण करने में मदद करते हैं। जाहिर है, यह करियर आपको प्रकृति के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका तो देता ही है, साथ ही रोमांचक भी है। अगर आप ऐसे ही रोमांचक करियर की तलाश में हैं, तो इस फील्ड से जुड़ सकते हैं।

क्या है वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशन

वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशन के अंतर्गत विशेषज्ञ पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करके उनके कारणों की खोज करते हैं। साथ ही वे वाइल्डलाइफ को सहेजने यानी कन्जर्व करने की कोशिश भी करते हैं। जब भी ऐसी जगहों पर कोई निर्माण या दूसरी गतिविधि होती है, तो पहले इन्हीं विशेषज्ञों की अनुमति ली जाती है। यही नहीं, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण का काम भी यही एक्सपर्ट्स करते हैं। इन्हीं विशेषज्ञों को कहा जाता है, वाइल्डलाइफ कन्जर्वेशनिस्ट।

कौन-से कोर्सेज

इस फील्ड में करियर बनाने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय होने जरूरी हैं। आप वाइल्डलाइफ साइंस, इकोलॉजी, एन्वायर्नमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके बाद इन्हीं विषयों से पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी की जा सकती है। इसके अलावा आप वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फील्ड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करवाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान विद्यार्थियों को कैम्पिंग के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलता है। वहीं कुछ इंस्टीट्यूट्स वाइल्डलाइफ फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, जिसे आर्ट ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं।

क्या हैं संभावनाएं

आप राष्ट्रीय उद्यानों (नेशनल पार्क्स) व वन्य जीव अभयारण्यों (वाइल्डलाइफ सैंक्चुरीज) से जुड़कर काम कर सकते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूटीआई, पेटा और वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपना करियर बना सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी कई जॉब्स हैं। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षा देकर बेहतरीन और प्रतिष्ठित जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप बतौर साइंटिस्ट, रिसर्चर, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट और एनालाइजर अपना करियर बना सकते हैं और वाइल्डलाइफ से जुड़े अलग-अलग तथ्यों को सामने ला सकते हैं।

सैलरी कितनी

सरकारी रिसर्च और साइंस इंस्टीट्यूट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स की शुरुआती सैलेरी 25,000 रुपए है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग में आपकी शुरुआत 50,000 रुपए से होगी। परमानेंट जॉब और बढ़ते अनुभव से आपका वार्षिक पैकेज 30-35 लाख तक हो सकता है।

कैसी होनी चाहिए स्किल्स

सबसे पहले तो आपके अंदर प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति लगाव होना चाहिए क्योंकि तभी आप कठिन परिस्थितियों में भी काम कर पाएंगे। वैसे भी जब तक आप अपने करियर को लेकर पैशनेट नहीं होंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपमें समस्याओं के बारे में रिसर्च करने और उनका विश्लेषण करने का धैर्य होना चाहिए। एडवेंचरस होना और खतरों के लिए तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है।

कॅरियर में मददगार होंगे यह पॉइंट्स

आप शिक्षा के जिस भी स्तर पर हैं, उसी अनुरूप आप अपने कॅरियर के चुनाव में विभिन्न उपायों को आजमा सकते हैं। मान लीजिये कि आप दसवीं में हैं, तो मंजिल के चुनाव के लिए आप अपने टीचर, पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा कॅरियर आपके लिए किस ढंग से लाभकारी होगा?

यह एक जांचा परखा तथ्य है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने कॅरियर के शुरुआती दौर में ही सही फैसले लेकर उचित कॅरियर का चुनाव कर लिया, तो उसकी आगे की राह काफी आसान हो जाती है। कहते हैं दुनिया में हर व्यक्ति सफर करता है, किंतु मंजिल पर पहुंचते बहुत कम लोग हैं। आप कह सकते हैं कि सही मंजिल पर कैसे पहुंचा जाए, तो इसमें यही बात समझने योग्य है कि सही मंजिल पर पहुंचने के लिए मंजिल का चुनाव, उसकी पहचान जरूरी है।

कॅरियर रुपी मंजिल का चुनाव कैसे करें?

क्या आप दसवीं में हैं? या फिर आप 12वीं में अथवा ग्रेजुएशन कर चुके हैं? आप शिक्षा के जिस भी स्तर पर हैं, उसी अनुरूप आप अपने कॅरियर के चुनाव में विभिन्न उपायों को आजमा सकते हैं। मान लीजिये कि आप दसवीं में हैं, तो मंजिल के चुनाव के लिए आप अपने टीचर, पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा कॅरियर आपके लिए किस ढंग से लाभकारी होगा? खासकर दसवीं के बाद आपको साइंस या आर्ट्स में से कोई एक स्ट्रीम चुननी होती है। इसी तरह से अगर आप 12वीं में हैं तो आप साइंस में भी मैथ्स या बायो लेकर चलना होता है अथवा आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर पढ़ाई करना होता है। वस्तुत: यहां से कॅरियर एक दिशा ले लेता है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं या फिर एनडीए अथवा दूसरे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन में तो आपकी समझ पूरी तरह से खुल चुकी होती है और आपको पूरी तरह से पता होता कि हकीकत में करना क्या है। बस कई लक्ष्यों के बीच में खुद को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको आपकी मंजिल से दूर कर देगा। ध्यान रखना चाहिए कि भेड़ चाल से बचना कैसे है और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क के अनुसार चुनना चाहिए। जब आप मंजिल को ठीक से पहचान लेते हैं तब आपका काम काफी आसान हो जाता है।

जुट जाएँ मंजिल तक पहुंचने में

जब एक बार मंजिल की पहचान हो जाती है, फिर आप तब तक ना रूकें, जब तक मंजिल पर पहुंच ना जाएँ। ध्यान रखें, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि बैठे रहने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर अपनी मंजिल को आपने पहचान लिया है तो आपको तेजी से और मजबूत कदमों से उस और बढ़ने की आवश्यकता होती है। इसके लिए न केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज करें, बल्कि ऑनलाइन की दुनिया से अपने आपको लगातार अपडेट करें। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्स में प्रवेश ले लिया है, बल्कि अपनी स्किल को निखारने के लिए आपको ऑनलाइन एजुकेशन, कोर्सेज के माध्यम से तमाम स्किल विकसित करनी होगी। इसके लिए कई फ्री तो कई पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसे आप अपनी रूचि के अनुसार चुन सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है खुद को लगातार अपग्रेड करना चाहिए। हालांकि रेगुलर पढ़ाई की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर संस्थान का चुनाव करना चाहिए और उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड को भी अपनी नजर में रखना चाहिए।

इनोवेशन को अहमियत दें

जापान के बारे में हम आप बचपन से सुनते आए हैं कि वहां बच्चे पढ़ाई के दिनों से ही प्रायोगिक चीजों में रूचि लेने लगते हैं और दसवीं तक आते आते तो घड़ी, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि विकसित करने लगते हैं। भारत में अभी इस तरह का माहौल पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, किंतु एक सच यह भी है कि भारत में ही कई सारे छोटे बच्चे कोडिंग के माध्यम से तमाम प्रोग्राम लिखते हैं, तो कई अपनी क्रिएटिव थॉट से वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे कई यूट्यूब चैनल आप देखते ही होंगे, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने कितना कमाल किया है। तो आप भी अपने स्तर पर कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढें और हां इसका इंतजार ना करें कि अब अमुक पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी तो आप अपने कॅरियर को सेट करेंगे। इसकी बजाय पढ़ाई के कोर्सेज के दौरान ही आप खुद को स्टेबल करने की कोशिश करें। आप एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो भविष्य में आपके लिए यह काफी अच्छा रहेगा। आप जॉब करें या फिर अपना बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से आप खुद को सफल इंसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।

भटकाव से बचें

आज के समय में तमाम एक्सपर्ट और रिसर्च इस बात के प्रति जागरूक करते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में आपका समय बहुत खराब होता है। छोटे-छोटे बच्चे यूट्यूब और दूसरी ऑनलाइन साइट्स पर, गेम्स पर अपने जीवन का कीमती समय नष्ट करते हैं। यह धीरे-धीरे उनकी आदत बन जाती है और जो इंटरनेट अच्छी जानकारियों का सोर्स हो सकता है, उसे वह समय नुकसान करने का माध्यम बना लेते हैं। ना केवल बच्चे, बल्कि युवा भी इस पर अपना अच्छा खासा समय बर्बाद करते हैं, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के समय में समय बर्बाद करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी इंटरनेट ही बन गया है। इसके लिए आप अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे तो आपका कॅरियर सही दिशा में अवश्य ही आगे बढ़ेगा। पहले समय पास करने का काम नालायक दोस्त किया करते थे, लेकिन कइयों की लाइफ में अब यह स्थान इंटरनेट में ले लिया है। हालाँकि, कई लोग इंटरनेट को 'सच्चा दोस्त' बनाकर अपनी जिन्दगी में बड़े बड़े मुकाम इसी की सहायता से प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए इस के सकारात्मक पक्ष पर फोकस करें और भटकाव से बचने के लिए इंटरनेट पर पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।